FREE DEMO SAMPLE

Guessing Paper 2026-27 Demo Set

B.A. · Semester 1 · Introduction to Political Theory

SNPV Raigarh — शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़

यह सिर्फ़ एक डेमो सेट है 📘

इस डेमो से आप हमारे उत्तरों की क्वालिटी और पेपर का फ़ॉर्मेट देख सकते हैं। **असली 3 पूरे Guessing Paper सेट** (Set A, B, C) सिर्फ़ **Pariksha Pass App** में मिलते हैं:

- हर विषय के **3 पूरे सेट** — Most Probable, Highly Likely और Alternate
- हर प्रश्न का **सटीक मॉडल उत्तर** — हिंदी और English दोनों में
- **Year Tag** — जो प्रश्न पहले यूनिवर्सिटी परीक्षा में आ चुके हैं
- आपकी **यूनिवर्सिटी के पैटर्न** पर — पूरा सिलेबस कवर

▶ Pariksha Pass App डाउनलोड करें
यहाँ टैप करें — Google Play पर उपलब्ध

QR स्कैन करें

इस डेमो के प्रश्न असली Set A/B/C से नहीं लिए गए हैं। कोई भी पेपर परीक्षा में प्रश्न आने की गारंटी नहीं देता — इसे पाठ्यपुस्तक के साथ अभ्यास के लिए उपयोग करें। · Free sample shared on cguniversities.com

DEMO SAMPLE – NOT FROM THE ACTUAL SETS
डेमो नमूना – वास्तविक सेटों के प्रश्न इसमें नहीं हैं

Paper Code: **PSSC 01**
Demo Set

Roll No. | | | | | | | | | |

SHAHEED NANDKUMAR PATEL VISHWAVIDYALAYA, RAIGARH (C.G.)
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

B.A. (First Semester) Examination, Nov.–Dec. 2026
बी.ए. (प्रथम सेमेस्टर) परीक्षा, नवम्बर–दिसम्बर 2026

INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY
राजनीतिक सिद्धांत का परिचय

Time / **समय** : 3 Hours	Maximum Marks / **पूर्णांक** : 70

DEMO SAMPLE – not from the actual sets · prepared by Online Student Seva to show the paper format and answer quality · not an official University question paper

Instructions:

1. Section A: Q.1 (objective) is compulsory. All 5 short-answer questions in Q.2 are compulsory.
2. Section B: attempt **one** question from each unit (Q.3 to Q.6); each has an internal choice.
3. Figures in the right margin show full marks. Draw neat, labelled diagrams wherever necessary.

निर्देश : खण्ड-अ में प्रश्न 1 अनिवार्य है; प्रश्न 2 के सभी 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। खण्ड-ब में प्रत्येक इकाई से **एक** प्रश्न हल करें (प्रश्न 3 से 6), सभी में आंतरिक विकल्प है। दाईं ओर के अंक पूर्णांक दर्शाते हैं। आवश्यकतानुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाएँ।

SECTION – A / खण्ड – अ

Q.1 **Choose the correct answer.** सही उत्तर चुनिए। 10 × 1 = 10

(1) The word 'politics' is derived from the Greek word 'polis', which means:
'पॉलिटिक्स' (राजनीति) शब्द यूनानी शब्द 'पोलिस' से बना है, जिसका अर्थ है:

(a) City-state / नगर-राज्य (b) Law / कानून
(c) Citizen / नागरिक (d) Assembly / सभा

(2) A political theory that deals with 'what ought to be', that is, with values such as justice, liberty and equality, is called:
वह राजनीतिक सिद्धांत जो 'क्या होना चाहिए' अर्थात न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों से संबंधित है, कहलाता है:

(a) Empirical theory / अनुभवमूलक सिद्धांत (b) Normative theory / आदर्शात्मक (मानकीय) सिद्धांत
(c) Descriptive theory / वर्णनात्मक सिद्धांत (d) Statistical theory / सांख्यिकीय सिद्धांत

(3) Which of the following is NOT an essential element of the state?
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है?

(a) Population / जनसंख्या (b) Territory / भू-भाग
(c) Government / सरकार (d) Political party / राजनीतिक दल

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

(4) The Peace of Westphalia (1648) is regarded as the starting point of:
वेस्टफेलिया की संधि (1648) को किसकी शुरुआत माना जाता है?

(a) The League of Nations / राष्ट्र संघ
(b) The feudal system / सामंती व्यवस्था
(c) The modern system of sovereign nation-states / संप्रभु राष्ट्र-राज्यों की आधुनिक व्यवस्था
(d) The United Nations / संयुक्त राष्ट्र

(5) The word 'nation' comes from the Latin word 'natio', which means:
'नेशन' (राष्ट्र) शब्द लैटिन शब्द 'नैशियो' से बना है, जिसका अर्थ है:

(a) Birth or race / जन्म या वंश
(b) Land / भूमि
(c) Law / कानून
(d) Government / सरकार

(6) John Rawls developed the idea of 'justice as fairness' in his book:
जॉन रॉल्स ने 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' का विचार किस पुस्तक में दिया?

(a) Leviathan / लेवियाथन
(b) A Theory of Justice (1971) / ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971)
(c) The Republic / द रिपब्लिक
(d) On Liberty / ऑन लिबर्टी

(7) The principle of 'one person, one vote' is an expression of:
'एक व्यक्ति, एक मत' का सिद्धांत किसकी अभिव्यक्ति है?

(a) Economic equality / आर्थिक समानता
(b) Social equality / सामाजिक समानता
(c) Political equality / राजनीतिक समानता
(d) Natural equality / प्राकृतिक समानता

(8) The idea of 'popular sovereignty', that supreme power belongs to the people and is expressed through the general will, is associated with:
'लोकप्रिय संप्रभुता' का विचार, कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है और सामान्य इच्छा से व्यक्त होती है, किससे जुड़ा है?

(a) Austin / ऑस्टिन
(b) Bodin / बोदाँ
(c) Hobbes / हॉब्स
(d) Rousseau / रूसो

(9) The power of the courts to declare a law unconstitutional is known as:
न्यायालयों द्वारा किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति कहलाती है:

(a) Judicial review / न्यायिक पुनर्विलोकन
(b) Judicial activism / न्यायिक सक्रियता
(c) Writ jurisdiction / रिट अधिकारिता
(d) Impeachment / महाभियोग

(10) Which of the following is a feature of a totalitarian state?
निम्नलिखित में से कौन-सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता है?

(a) Rule of law and a free press / विधि का शासन और स्वतंत्र प्रेस
(b) A single party that controls every sphere of life / एकमात्र दल जो जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करता है
(c) An independent judiciary / स्वतंत्र न्यायपालिका
(d) Competitive multi-party elections / प्रतिस्पर्धी बहुदलीय चुनाव

Q.2 Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 × 4 = 20

(a) What is political theory? State its main functions. 4
राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख कार्य बताइए।

(b) Distinguish between a nation and a state. 4
राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

(c) State John Rawls's two principles of justice. 4
जॉन रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांत बताइए।

(d) Explain Rousseau's concept of the general will. 4
रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा समझाइए।

(e) Distinguish between a flexible and a rigid constitution. 4
लचीले और कठोर संविधान में अंतर कीजिए।

SECTION – B / खण्ड – ब

Long answer questions · one question from each unit with internal choice / **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

Q.3 Discuss the relationship of Political Science with History, Economics, Sociology, Psychology and Law. 10
राजनीति विज्ञान का इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और विधि से संबंध स्पष्ट कीजिए।

OR / अथवा

Is Political Science a science? Discuss with arguments for and against.
क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? पक्ष और विपक्ष के तर्कों सहित चर्चा कीजिए।

Q.4 Explain the Divine Origin Theory of the state. Examine its merits and criticisms. 10
राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके गुण-दोषों की समीक्षा कीजिए।

OR / अथवा

What is nationalism? Discuss its elements, types, merits and demerits.
राष्ट्रवाद क्या है? इसके तत्त्वों, प्रकारों, गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए।

Q.5 What is equality? Explain its different types and discuss its relation with liberty. 10
समानता क्या है? इसके विभिन्न प्रकार बताइए तथा स्वतंत्रता से इसके संबंध की चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

What is civil disobedience? Explain its essential conditions, distinguish it from ordinary crime and revolution, and discuss whether it is justified in a democracy.
सविनय अवज्ञा क्या है? इसकी आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए, इसे साधारण अपराध और क्रांति से अलग कीजिए तथा बताइए कि लोकतंत्र में यह कहाँ तक उचित है।

Q.6 What is totalitarianism? Explain its main features and distinguish it from democracy. 10
सर्वाधिकारवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए और इसे लोकतंत्र से अलग कीजिए।

OR / अथवा

Explain the theories of representation and compare the majority system with proportional representation.
प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा बहुमत प्रणाली की तुलना आनुपातिक प्रतिनिधित्व से कीजिए।

— END OF QUESTION PAPER · प्रश्न-पत्र समाप्त —

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Syllabus Coverage & Reference Books पाठ्यक्रम कवरेज एवं संदर्भ ग्रंथ

This paper follows the official **Introduction to Political Theory** syllabus (PSSC 01) of the Chhattisgarh Higher Education Department (NEP-2020). The table shows what each unit contains and where this paper tests it.

Unit	Syllabus content (as prescribed)	Questions in this set
1	**Political Science - Initial** Political science: concept, nature, scope; power, authority (meaning, characteristics, types); legitimacy and its relationship with power and authority; methods of study of political science; behaviouralism and post-behaviouralism. **राजनीति विज्ञान - प्रारंभिक** — राजनीति विज्ञान: अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र; शक्ति, सत्ता (अर्थ, विशेषताएँ, प्रकार); वैधता तथा शक्ति, सत्ता और वैधता का संबंध; राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ; व्यवहारवाद एवं उत्तर-व्यवहारवाद।	Q.1(1), Q.1(2), Q.2(a), Q.3
2	**State** State: concept, development, essential elements; theories of origin of state (divine, force, social contract, evolutionary); theories of functions of state (Marxist, liberal, neo-liberal, pluralist); law: definition, sources, classification; public welfare state; nationalism: concept and types. **राज्य** — राज्य: अवधारणा, विकास, अनिवार्य तत्व; राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत (दैवीय, शक्ति, सामाजिक समझौता, विकासवादी); राज्य के कार्यों के सिद्धांत (मार्क्सवादी, उदारवादी, नव-उदारवादी, बहुलवादी); विधि: परिभाषा, स्रोत, वर्गीकरण; लोक कल्याणकारी राज्य; राष्ट्रवाद: अवधारणा एवं प्रकार।	Q.1(3), Q.1(4), Q.1(5), Q.2(b), Q.4
3	**Concepts** Sovereignty: concept, types, characteristics; legal (monistic) and pluralist principles of sovereignty; rights: meaning, types, major theories; duties; freedom: meaning, types, positive and negative theory; equality and its relation to freedom; political obligation; justice: concept, types; democracy: concept, types, merits, demerits, principles and conditions for success. **अवधारणाएँ** — संप्रभुता: अवधारणा, प्रकार, विशेषताएँ; संप्रभुता के विधिक (एकलवादी) एवं बहुलवादी सिद्धांत; अधिकार: अर्थ, प्रकार, प्रमुख सिद्धांत; कर्तव्य; स्वतंत्रता: अर्थ, प्रकार, सकारात्मक एवं नकारात्मक सिद्धांत; समानता और स्वतंत्रता से उसका संबंध; राजनीतिक दायित्व; न्याय: अवधारणा, प्रकार; लोकतंत्र: अवधारणा, प्रकार, गुण, दोष, सिद्धांत तथा सफलता की आवश्यक शर्तें।	Q.1(6), Q.1(7), Q.1(8), Q.2(c), Q.2(d), Q.5
4	**State in Function** Forms of government: unitary and federal, parliamentary and presidential; totalitarianism; organs of government (legislature, executive, judiciary); separation of powers and checks and balances; constitution: meaning and kinds; political party; pressure groups; public opinion; social justice; theories of representation. **क्रियाशील राज्य** — शासन के रूप: एकात्मक एवं संघात्मक, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक; सर्वाधिकारवाद; सरकार के अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका); शक्ति-पृथक्करण एवं नियंत्रण-संतुलन; संविधान: अर्थ एवं प्रकार; राजनीतिक दल; दबाव समूह; लोकमत; सामाजिक न्याय; प्रतिनिधित्व के सिद्धांत।	Q.1(9), Q.1(10), Q.2(e), Q.6

Books recommended in the syllabus (derive your answers from these) / पाठ्यक्रम में अनुशंसित पुस्तकें

Text books:

- S.P. Varma - Modern Political Theory; Vikas Publishing House, New Delhi (English & Hindi medium)

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- Pukhraj Jain - Rajniti Vigyan ke Siddhant (Political Science Principles); Sahitya Bhawan Publications, Agra (Hindi medium)
- Rajeev Bhargava and Ashok Acharya (eds.) - Political Theory: An Introduction; Pearson Longman, New Delhi
- Eddy Asirvatham and K.K. Misra - Political Theory; S. Chand Publishing, New Delhi

Reference books:

- O.P. Gauba - An Introduction to Political Theory; Macmillan Publishers India, New Delhi
- J.C. Johari - Principles of Modern Political Science; Sterling Publishers, New Delhi
- A.C. Kapur - Principles of Political Science; S. Chand Publishing, New Delhi
- A. Appadorai - The Substance of Politics; Oxford University Press, New Delhi

Always use the latest edition. Model answers in this paper follow the standard university textbooks listed above, in simplified exam-ready form. / नवीनतम संस्करण का प्रयोग करें।

Important advice / ज़रूरी सलाह

This paper is based on the NEP syllabus and high-probability topic coverage, and it covers the topics most likely to be asked. However, **do not depend on this paper alone** — prepare the complete syllabus from your text book. Use this paper to practise writing and time management.

यह पेपर एनईपी पाठ्यक्रम और अधिक संभावित टॉपिक कवरेज पर आधारित है तथा अधिक संभावित टॉपिक कवर करता है। फिर भी **केवल इसी पर निर्भर न रहें** — अपनी पाठ्यपुस्तक से पूरा पाठ्यक्रम तैयार करें। इस पेपर का उपयोग लेखन-अभ्यास व समय-प्रबंधन के लिए करें।

DEMO SAMPLE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

PART – I : English Medium – Model Answers

Every answer is written to the marks allotted — learn the structure, then write in your own words.

Section A · Q.1 : Answer key

No.	Ans.	Correct option	Explanation
1	(a)	City-state	'Polis' was the small self-governing Greek city-state that Aristotle studied; politics is therefore the study of the affairs of the polis.
2	(b)	Normative theory	Normative theory judges the state and politics against ideals and values; empirical theory describes and explains what actually exists.
3	(d)	Political party	The four essential elements are population, territory, government and sovereignty. Political parties matter in a democracy but are not needed for a state to exist.
4	(c)	The modern system of sovereign nation-states	The treaties ended the Thirty Years' War and established the principle of sovereign states with fixed territories, the base of the modern state system.
5	(a)	Birth or race	'Natio' means birth or race; a nation was first a group of people of common descent and now means a people bound by shared history, culture and sentiment.
6	(b)	A Theory of Justice (1971)	Rawls set out justice as fairness, the original position and the veil of ignorance in 'A Theory of Justice' (1971).
7	(c)	Political equality	Equal voting rights for every adult citizen regardless of wealth, caste or sex is political equality.
8	(d)	Rousseau	Rousseau's 'The Social Contract' (1762) places sovereignty in the people and identifies it with the general will.
9	(a)	Judicial review	Judicial review lets the judiciary test laws and executive acts against the constitution and strike down those that violate it.
10	(b)	A single party that controls every sphere of life	A totalitarian state is marked by one ruling party, one ideology and total control over politics, economy, media and private life.

Section A · Q.2 : Short answers

Q.2(a) — 4 marks · ≈ 100–120 words

What is political theory? State its main functions.

Political theory is the systematic study of the ideas and principles that explain how political life is organised and how it ought to be organised. It deals with concepts such as the state, power, sovereignty, rights, liberty, equality, justice and democracy.

FUNCTIONS OF POLITICAL THEORY

- **Explanation:** it explains why political institutions arise and how they work.
- **Evaluation:** it judges laws and institutions by values such as justice and freedom.
- **Prescription:** it suggests how political life can be improved.
- **Clarification:** it gives precise meanings to concepts so that debate is clear.
- **Guidance:** it guides citizens, leaders and reformers in action.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Thus political theory joins facts with values; without it, politics would be only a struggle for power.

Q.2(b) 4 marks · ≈ 100–120 words

Distinguish between a nation and a state.

A **state** is a legal-political organisation with population, a defined territory, a government and sovereignty. A **nation** is a community of people who feel united by common history, culture, language or sentiment, and who think of themselves as one people.

Basis	Nation	State
Nature	Cultural and psychological unity	Legal and political organisation
Essential element	Feeling of oneness	Territory and sovereignty
Territory	May not have a fixed territory (e.g. the Kurds)	Must have a defined territory
Sovereignty	Not necessary	Essential
Membership	Based on sentiment	Based on citizenship

One nation may be divided into several states (Korea), and one state may contain many nations (India has one state with many communities); a nation-state, like Japan, is where the two largely coincide.

Q.2(c) 4 marks · ≈ 100–120 words

State John Rawls's two principles of justice.

In *A Theory of Justice* (1971) John Rawls argued that just principles are those free and rational people would choose in an imaginary **original position**, behind a **veil of ignorance**, where nobody knows his own class, talents or religion.

THE TWO PRINCIPLES

1. **Equal basic liberties:** every person has an equal right to the widest set of basic liberties compatible with the same liberties for all.
2. **Social and economic inequalities** are acceptable only if (a) they work to the greatest benefit of the **least advantaged**, known as the **difference principle**, and (b) the offices and positions are open to all under **fair equality of opportunity**.

The first principle has priority over the second.

Q.2(d) 4 marks · ≈ 100–120 words

Explain Rousseau's concept of the general will.

In *The Social Contract* (1762) Rousseau held that legitimate state authority rests on the **general will**, the community's will for the common good.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

MEANING AND FEATURES

- The general will is not the **will of all**, which is only the sum of selfish private wills; it is what every citizen wants as a member of the community.
- It is **always right** (aimed at the common good), **indivisible** and **inalienable**.
- Sovereignty belongs to the people; the government is only its agent.
- One who refuses to obey may be "forced to be free", since he follows a law he helped to make.

Critics fear it can justify majority tyranny, yet it underlies popular sovereignty and modern democracy.

Q.2(e) 4 marks · ≈ 100–120 words

Distinguish between a flexible and a rigid constitution.

A **flexible constitution** can be amended by the ordinary law-making procedure, whereas a **rigid constitution** needs a special and more difficult procedure for amendment.

Basis	Flexible constitution	Rigid constitution
Amendment	Same process as an ordinary law	Special majority, ratification or referendum
Adaptability	Changes quickly with the times	Changes slowly
Stability	Less stable, open to hasty change	More stable and secure
Protection of rights	Weaker	Stronger
Example	United Kingdom	United States

India follows a **mixed** course: some parts of the Constitution can be amended by a simple majority, others need a special majority, and some also need ratification by half of the State legislatures (Article 368). A good constitution balances stability with adaptability.

Section B : Long answers

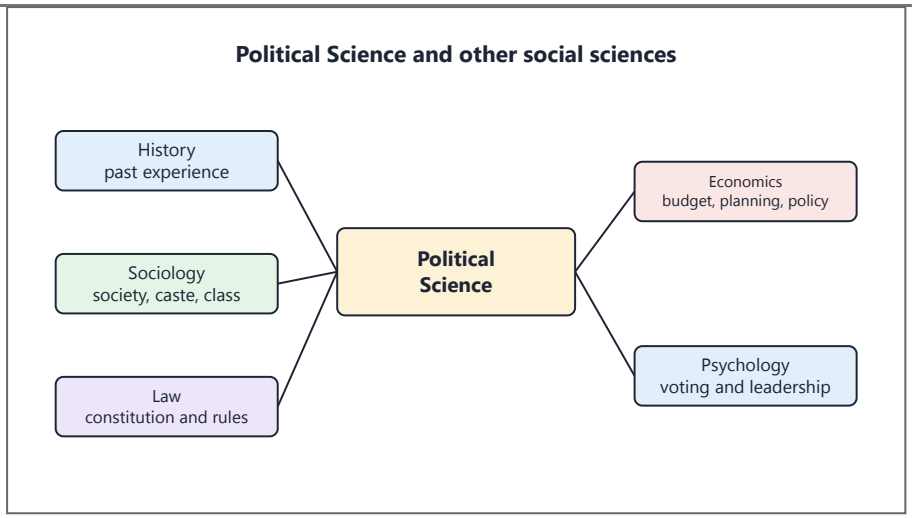
Q.3 · Unit 1 10 marks · ≈ 600–700 words

Discuss the relationship of Political Science with History, Economics, Sociology, Psychology and Law.

INTRODUCTION

Political Science studies the state, government, power and the political behaviour of people. Human life, however, is not divided into watertight compartments. Political, economic, social and legal events are tied together, and so the social sciences borrow from one another. A student of politics who ignores the neighbouring disciplines sees only a part of the picture. The relationship with each major discipline is explained below.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Political Science and its neighbouring social sciences

1. POLITICAL SCIENCE AND HISTORY

History records the past of states, rulers, wars and revolutions. Political Science studies the present and the future of the state. The old saying of J. R. Seeley is often quoted: *"History without Political Science has no fruit; Political Science without History has no root."*

- History supplies the raw material: the French Revolution, the Russian Revolution and the Indian freedom movement are all facts that political theorists study.
- Political Science analyses that material, draws lessons and builds concepts such as sovereignty, nationalism and democracy.
- Institutions such as Parliament or the federal system cannot be understood without knowing how they developed.

2. POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS

Early thinkers called the subject "political economy"; Adam Smith's *Wealth of Nations* (1776) is a famous example. Even today the two are closely linked.

- Economic power shapes political power: wealthy groups and industries influence law-making, funding and policy.
- Political decisions shape the economy: budgets, taxation, subsidies and planning are decided by governments. India's 1991 reforms of liberalisation are a political decision with an economic effect.
- Elections are often fought on economic issues such as prices, employment and welfare.

3. POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY

Sociology studies society as a whole: its groups, customs, family, caste and class. The state is only one institution within society, so Political Science depends on sociology.

- Social structure affects politics: caste, religion, language and region influence voting and party formation in India.
- Politics changes society: laws abolishing untouchability or protecting women's rights change social life.
- Topics such as pressure groups, political socialisation and social movements belong to both disciplines.

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

4. POLITICAL SCIENCE AND PSYCHOLOGY

Psychology studies the mind and behaviour of individuals. Graham Wallas's *Human Nature in Politics* (1908) argued that politics cannot be understood without understanding human motives, and Harold Lasswell's *Psychopathology and Politics* (1930) applied psychology to political leaders.

- Voting behaviour, public opinion, propaganda and leadership style are explained by attitudes, emotions and perceptions.
- The behavioural approach in Political Science grew out of this link.

5. POLITICAL SCIENCE AND LAW

Law is the set of rules enforced by the state, so the two are very close.

- The Constitution, the main subject of Political Science, is also the highest law.
- Political Science asks why laws should be obeyed and what makes them just; Law explains what the rules are and how they are applied by courts.
- Concepts such as sovereignty, rights, the rule of law (Article 14 in India) and judicial review are shared.
- Yet they differ: Law tells what *is* the rule, while Political Science also asks what *ought* to be the rule.

COMPARISON AT A GLANCE

Discipline	Focus	Link with Political Science
History	The past	Gives facts and lessons
Economics	Wealth and production	Policy, budget, class interests
Sociology	Society and groups	Social basis of politics
Psychology	Mind and behaviour	Voting, opinion, leadership
Law	Rules and courts	Constitution, rights, justice

CONCLUSION

Political Science stands at the meeting point of all social sciences. It borrows facts from history, models from economics, social context from sociology, behavioural insights from psychology and rules from law, and in return gives them an understanding of the state and power. A modern student therefore needs an interdisciplinary outlook, and this is why the subject is now studied with comparative and behavioural methods.

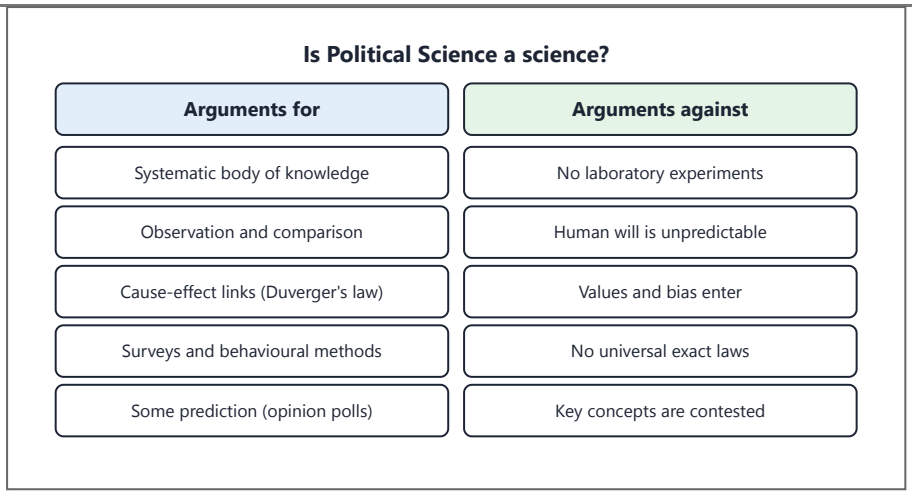
Q.3 (OR) · Unit 1 10 marks · ≈ 600–700 words

Is Political Science a science? Discuss with arguments for and against.

INTRODUCTION

Whether Political Science deserves to be called a "science" is an old debate. A natural science such as physics is marked by systematic observation, experiment, exact laws and the power of prediction. The question is how far the study of the state and of political behaviour meets these tests. Aristotle called politics the "master science" because it governs all other human activities, but modern writers divide into two camps.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Is Political Science a science?

MEANING OF "SCIENCE"

In the strict sense, a science is a body of knowledge that is (i) systematic and organised, (ii) based on observation and evidence, (iii) tested by experiment, (iv) able to discover universal cause-and-effect laws, and (v) able to predict future events. Judged by these tests, the subject can be examined in two ways.

ARGUMENTS IN FAVOUR

- **Systematic knowledge:** Political Science has an organised body of concepts, facts and theories on the state, government, rights and political parties.
- **Observation and comparison:** Scholars collect facts from constitutions, elections and institutions and compare many countries, as in the comparative method.
- **Cause-effect relationships:** Some regularities have been noticed. Maurice Duverger's observation (often called Duverger's law) says that the single-member plurality system tends to produce a two-party system.
- **Behavioural revolution:** After the Second World War, writers in the United States such as David Easton and Robert Dahl began using surveys, statistics and interviews to study voting, opinion and decision making.
- **Prediction:** Opinion polls and exit polls try to forecast election results, and political risk analysts forecast instability.
- **Self-correcting method:** theories are tested against new evidence and revised.

ARGUMENTS AGAINST

- **No laboratory experiments:** a political scientist cannot repeat a revolution or an election under controlled conditions as a chemist repeats a reaction.
- **Unpredictable human will:** people have free will and change their minds, so the same cause may not give the same effect. Poll forecasts sometimes fail.
- **Values and bias:** the researcher is also a citizen with beliefs, so complete objectivity is difficult. Terms like liberty, justice and democracy are interpreted differently by different thinkers.
- **No universal laws:** most findings hold only for a particular time and place, and exact laws like those of Newton do not exist.
- **Contested concepts:** even basic terms such as "power" or "state" have no single accepted definition.

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Too many variables:** politics is influenced by economy, culture, history and chance together, making it hard to isolate causes.

COMPARISON

Test of science	Natural science	Political Science
Experiment	Possible in laboratory	Rarely possible
Laws	Universal and exact	Tendencies, not exact
Prediction	Usually accurate	Limited and uncertain
Value-free	Largely yes	Difficult
Subject matter	Matter and energy	Thinking human beings

EVALUATION

The extreme answers are both unsatisfactory. If "science" means only the exact method of physics, then Political Science is not a science. But if science means a systematic, evidence-based and self-correcting search for knowledge, then it qualifies. A balanced view, held by many modern scholars, is that it is a **social science** or an "inexact science": it follows the scientific *method* and spirit, but cannot reach the same certainty because its subject is the changing human being. Medicine and meteorology are also called sciences although their predictions are imperfect.

CONCLUSION

Political Science is not an exact science like physics, yet it is more than mere opinion. It uses observation, comparison, statistics and theory to give reliable but limited and probable knowledge. Its progress through the behavioural and comparative approaches shows that it is steadily becoming more scientific, while its value dimension keeps it close to philosophy.

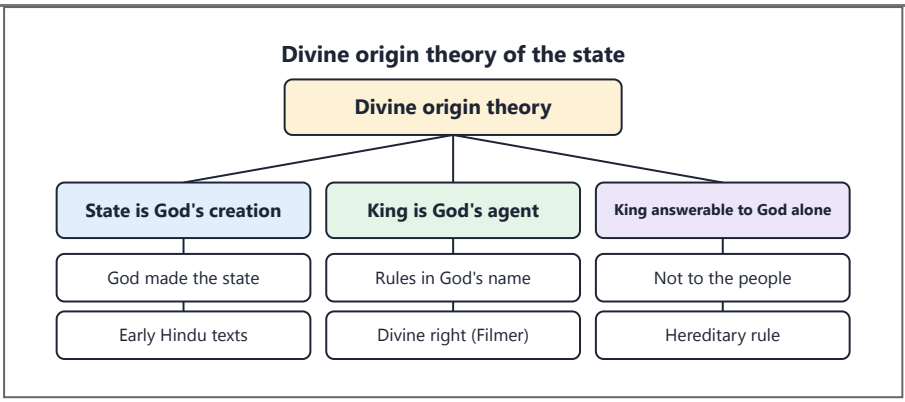
Q.4 · Unit 2 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the Divine Origin Theory of the state. Examine its merits and criticisms.

INTRODUCTION

The question "how did the state arise?" has been answered by many theories: divine, force, social contract, evolutionary and others. The Divine Origin Theory is the oldest. It holds that the state is not a human creation but was established by God, and that the ruler governs as God's agent. The theory was dominant in the ancient and medieval world, when religion controlled thought and politics.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Divine origin theory and its three forms

MAIN IDEAS OF THE THEORY

- The state is a divine institution, created by God for the good of mankind.
- The king is God's representative or even an incarnation, and rules by divine will.
- The king is answerable only to God, not to the people.
- Obedience to the king is a religious duty, and disobedience is a sin.

FORMS OF THE THEORY

1. **Theocracy:** God himself is the direct ruler, and the priests or prophets speak for him. The Jewish kingdom under its prophets and the medieval Papal claims are examples. In some ancient societies the ruler was considered a god.
2. **Divine right of kings:** God chooses the royal family, and the right to rule passes by heredity. In seventeenth-century England James I and Sir Robert Filmer (*Patriarcha*) argued that kings are accountable to God alone.
3. **Divine sanction:** the state is a human creation but is approved by God, so its authority is sacred. The Christian saying that "authority comes from God" and the ideas in some early Hindu texts, such as the king being protector under divine law, are placed here.

EXAMPLES FROM HISTORY

- In ancient Egypt the pharaoh was regarded as a god, and in Japan the emperor was long considered divine.
- In medieval Europe the Pope and the Church claimed a high role in deciding who could be crowned.
- In ancient India, texts like the Mahabharata describe the king as endowed with divine qualities, though many Indian thinkers also stressed *dharma* as a limit on royal power.

MERITS

- It made people obey authority, which brought order and discipline in early societies.
- It gave stability to rulers and reduced fear of rebellion.
- Religion linked the people with the ruler, creating loyalty and unity.
- It rightly noted the moral and spiritual basis of authority.

CRITICISMS

- **Unscientific:** there is no historical proof that God created any state; states grew through kinship, religion, force and need.
- **Supports despotism:** it allowed kings to rule without being answerable, and was used to defend tyranny.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Contrary to democracy:** it denies the sovereignty of the people and the right to question rulers.
- **Many religions, many states:** it cannot explain why different gods or religions support different, even rival, states.
- **Wrong in modern times:** the idea that a ruler is above the law is rejected by the principle of the rule of law and by constitutionalism.
- **Mixes politics with religion:** in a secular state, religion and political authority are kept separate.

DECLINE OF THE THEORY

The theory weakened after the Reformation, the Glorious Revolution of 1688 in England, and the American and French Revolutions. Thinkers such as Locke, who argued for consent and natural rights, replaced divine authority with popular consent.

COMPARISON WITH OTHER THEORIES

Theory	Source of the state	Status today
Divine origin	Will of God	Rejected as history
Force theory	Conquest and power	Partial truth only
Social contract	Agreement of people	Basis of democracy
Evolutionary	Gradual growth	Most accepted

CONCLUSION

The Divine Origin Theory has no value as a scientific explanation of how the state began, and it was harmful when it justified absolute rule. Its lasting contribution is the idea that political authority needs moral support and that power should serve a higher purpose. Modern political thought accepts the evolutionary view, in which the state grows from social needs and rests on the consent of the governed.

Q.4 (OR) · Unit 2 10 marks · ≈ 600–700 words

What is nationalism? Discuss its elements, types, merits and demerits.

INTRODUCTION

Nationalism is a strong feeling of loyalty and attachment to one's nation, together with the belief that the nation has a right to self-government. It is one of the most powerful political forces of the modern age. It united Italy and Germany in the nineteenth century, drove the freedom movements against colonial rule in Asia and Africa, and was also misused by dictators. It rests on the idea of the "nation", a people who feel they belong together.

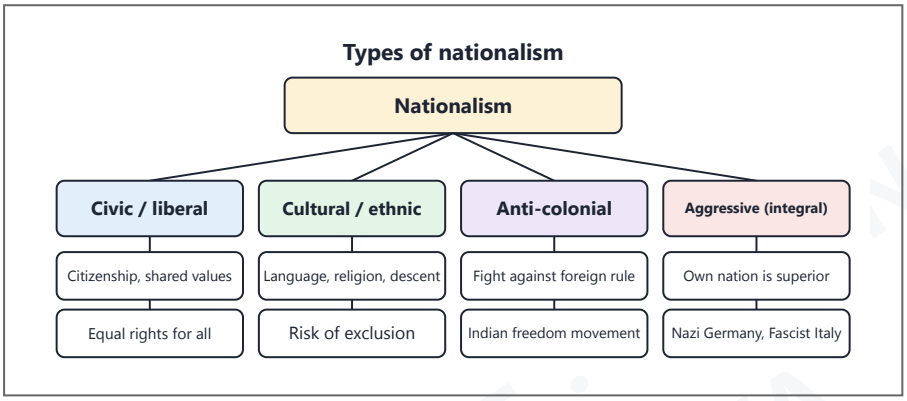
MEANING

Nationalism can be defined as a political and cultural sentiment in which people put the interests, unity and honour of their nation above narrower local loyalties. The nation-state, in which each nation has its own sovereign state, is its political aim. The word comes from the Latin *natio*, meaning birth or race.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

ELEMENTS THAT CREATE NATIONALISM

- **Common history and memories:** shared struggles and heroes, such as the 1857 revolt or the Salt March in India, strengthen belonging.
- **Common culture, language and religion:** these give a feeling of "we", though they are helpful, not essential. Switzerland has several languages but one nation.
- **Common territory:** attachment to a homeland.
- **Common political aspirations:** the wish to be free and to rule oneself.
- **Common economic interests and a shared enemy:** foreign rule often unites people.
- **Will to live together:** Ernest Renan said a nation is a "daily plebiscite", resting on the will to live together.



Types of nationalism

TYPES OF NATIONALISM

1. **Civic or liberal nationalism:** membership depends on citizenship and shared political values, not descent. The Indian Constitution, which gives equal rights to all, follows this idea. Mazzini, the Italian thinker, held that each nation should be free and that nations should cooperate.
2. **Cultural or ethnic nationalism:** the nation is defined by common language, religion or descent. It can preserve heritage but may exclude minorities.
3. **Anti-colonial nationalism:** the struggle of colonised peoples to get independence, as in India, Algeria and Vietnam.
4. **Aggressive or integral nationalism:** the nation is considered superior and expansion is justified. It led to Nazi Germany and Fascist Italy and to the Second World War.

MERITS

- It unites different groups and creates social solidarity and patriotism.
- It inspired freedom movements and ended colonial empires.
- It builds civic pride, discipline and sacrifice for the country.
- It supports economic and cultural development, for example the use of the national language and indigenous industry.
- It gives legitimacy to the nation-state and to democracy, since it rests on the idea that the people are sovereign.

DEMERITS

- **Aggressive nationalism leads to war,** as in the two World Wars.
- **Exclusion of minorities:** a narrow definition of the nation can create hatred of "outsiders", migrants or minorities.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Racial superiority:** it may breed prejudice and violence, as in Nazi doctrine.
- **Obstacle to world cooperation:** extreme nationalism opposes internationalism and global solutions to problems such as climate change.
- **Misuse by leaders:** politicians may use national feeling to hide failures and suppress dissent.
- **Separatism:** it can break up multi-ethnic states when groups demand their own nation.

INDIAN VIEW

Indian nationalism grew against British rule and was largely inclusive. Gandhi stressed non-violence and unity of all communities, and Tagore warned against aggressive nationalism. The Constitution reflects civic nationalism through equal citizenship, fundamental rights and secularism.

NATIONALISM AND INTERNATIONALISM

Basis	Nationalism	Internationalism
Loyalty	To the nation	To humanity
Aim	National freedom and unity	World peace and cooperation
Risk	Narrowness, conflict	Weakening of identity
Balance	Healthy when inclusive	Healthy when respects nations

CONCLUSION

Nationalism is neither wholly good nor wholly bad. When it is liberal, inclusive and respects the rights of others, it produces freedom, unity and progress. When it becomes aggressive and exclusive, it causes hatred and war. A mature nationalism therefore combines love of one's own nation with respect for other nations and for human rights.

Q.5 · Unit 3 10 marks · ≈ 600–700 words

What is equality? Explain its different types and discuss its relation with liberty.

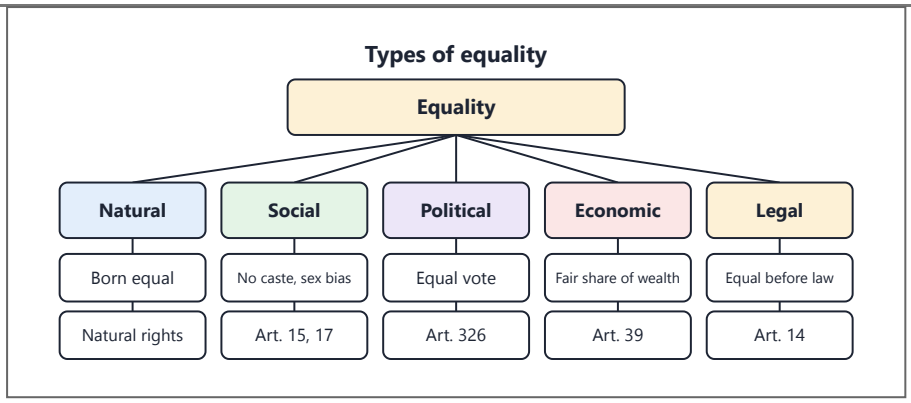
INTRODUCTION

Equality is one of the three ideals of the French Revolution (liberty, equality, fraternity) and a basic value of modern democracy. It does not mean that all people are identical in talent, height or income. It means that all human beings have equal worth and deserve equal respect, and that no one should be denied rights or opportunities because of birth, caste, sex, religion or wealth.

MEANING

Equality means the absence of unjust privileges and the presence of fair and adequate opportunities for all. Harold Laski stressed that equality means, first, the absence of special privilege and, second, adequate opportunities open to all. Two meanings are therefore usually separated: **formal equality** (the same rights and the same law for everyone) and **substantive equality** (special help to disadvantaged groups so that they can compete fairly).

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Types of equality and constitutional provisions

TYPES OF EQUALITY

1. **Natural equality:** all human beings are born equal and have equal natural rights. Rousseau and Locke argued this, though people differ in ability.
2. **Social equality:** no discrimination on grounds of caste, religion, sex, descent or place of birth. In India Article 15 prohibits discrimination and Article 17 abolishes untouchability.
3. **Civil or legal equality:** all are equal before the law and have equal protection of the laws. It is the rule of law, and Article 14 of the Indian Constitution declares it.
4. **Political equality:** every adult citizen has an equal right to vote and to contest elections, expressed as one person, one vote. Article 326 provides adult franchise in India.
5. **Economic equality:** a fair distribution of wealth and income and freedom from extreme poverty. It does not demand identical income, but Article 39 directs the state to avoid concentration of wealth and to give equal pay for equal work.
6. **Equality of opportunity:** everyone should have a fair chance in education and employment, as in Articles 16 and 21A, with reservation and affirmative action for backward groups.

RELATION BETWEEN LIBERTY AND EQUALITY

There are two traditions of thought.

1. Liberty and equality are opposed (the liberal view). Thinkers like Lord Acton and de Tocqueville feared that too much equality would reduce freedom. If the state enforces equal incomes, it must restrict the freedom of talented or hardworking persons to earn more. Equal outcomes can be achieved only by controlling choice, they argued.

2. Liberty and equality are complementary (the democratic and socialist view). Rousseau, Laski, R. H. Tawney and Ambedkar argued that liberty without equality is meaningless.

- Political liberty is empty if the poor cannot use it: a hungry person's freedom to vote is not equal to a rich person's influence.
- Economic inequality gives the rich power over the poor, so it destroys the liberty of the many.
- Equal opportunity is itself the condition for real freedom to develop one's abilities.
- Ambedkar warned that political democracy cannot last without social and economic democracy, and said that liberty, equality and fraternity form a "union of trinity"; one cannot be divorced from the others.

EVALUATION

The best resolution is that the two are interdependent. Complete equality of outcome would harm freedom and efficiency, while unlimited liberty would produce domination by the powerful. A just society therefore secures **equal liberty** for all: equal basic rights, equal opportunity and a

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

minimum standard of living, with room for differences earned by effort. Rawls's principles of justice express a similar balance.

COMPARISON

Aspect	Liberty	Equality
Core idea	Freedom from restraint and freedom to develop	Equal worth and equal chances
Main risk if extreme	Domination of the strong	Uniformity, loss of choice
Constitutional examples	Article 19	Articles 14-17

CONCLUSION

Equality is a necessary base of democracy, and it is meaningful only when it is joined with liberty. The Indian Constitution tries to achieve both through the Fundamental Rights and the Directive Principles. The aim is a society in which every person has the same dignity and the real chance to become what he or she can be.

Q.5 (OR) · Unit 3 10 marks · ≈ 600–700 words

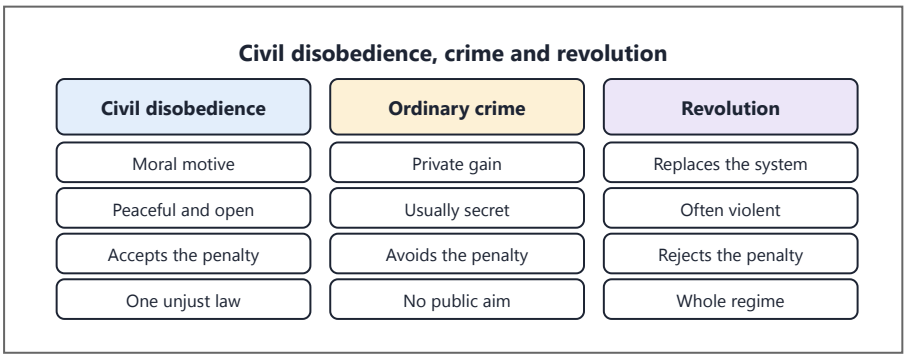
What is civil disobedience? Explain its essential conditions, distinguish it from ordinary crime and revolution, and discuss whether it is justified in a democracy.

INTRODUCTION

A citizen who disagrees with a law normally has lawful remedies: voting, petitions, public debate and the courts. Sometimes, however, a person believes that a law or policy is so unjust that he deliberately breaks it in public. This act is called **civil disobedience**. It raises a basic question of political theory: when, if ever, may a citizen morally disobey the state?

MEANING AND DEFINITION

Civil disobedience is the open, peaceful and conscientious breach of a law or policy, accepted along with its legal penalty, in order to draw attention to an injustice and bring about a change in the law. John Rawls, in *A Theory of Justice* (1971), describes it as a public, non-violent, conscientious and political act contrary to law, usually aimed at changing the law or the policy of the government. It differs from the private refusal of a *conscientious objector*, who only wishes to keep his own conscience clear and does not try to change the law.



Civil disobedience compared with ordinary crime and revolution

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

ESSENTIAL CONDITIONS

1. **Non-violence:** no harm to persons or property; the protest persuades, it does not coerce.
2. **Openness:** it is done publicly, not in secret, so that the authorities and the public know the reason.
3. **Conscientious motive:** it is aimed at a serious injustice and a public good, not at private gain.
4. **Acceptance of the penalty:** the protester does not run away from punishment; his willingness to suffer shows his sincerity and his respect for law as a whole.
5. **Last resort:** lawful remedies such as petitions, negotiation and the courts have usually been tried and have failed.
6. **Limited target:** it opposes one unjust law or policy, not the entire constitutional order.

ILLUSTRATIONS

- **Henry David Thoreau** refused to pay a poll tax, partly in protest against slavery and the Mexican War. He spent a night in jail (1846) and set out his ideas in the essay *Resistance to Civil Government* (1849), later known as *Civil Disobedience*.
- **Mahatma Gandhi** developed the method as *satyagraha*, or holding firmly to truth. It was used in Champaran (1917), in the Non-Cooperation Movement (1920-22) and in the Salt March from Sabarmati to Dandi (12 March to 6 April 1930), after which volunteers across India broke the salt law and accepted lathi blows and imprisonment without retaliation.
- **Martin Luther King Jr.** applied it in the Montgomery bus boycott (1955-56) and defended it in his *Letter from Birmingham Jail* (1963), arguing that a person who breaks an unjust law openly and accepts the penalty shows the highest respect for law.

DIFFERENCE FROM CRIME AND REVOLUTION

Basis	Civil disobedience	Ordinary crime	Revolution
Motive	Moral, public good	Private gain	Replace the whole system
Method	Peaceful and open	Usually secret	Often violent
Penalty	Accepted	Avoided	Not accepted
Target	One unjust law	None	The entire regime
Respect for law	Retained	Absent	Rejected

IS IT JUSTIFIED IN A DEMOCRACY?

In favour: obeying a gravely unjust law is itself a moral compromise; majorities can be mistaken or indifferent to minorities; and peaceful disobedience awakens public conscience, as Gandhi's movements did against colonial rule. Rawls adds that, in a nearly just society, it can strengthen justice by appealing to the majority's own sense of fairness.

Against: in a democracy there are lawful ways of changing laws; if every citizen decides which laws to obey, order would collapse; protest can slide into violence; and the disobedient person may be wrong about what is just.

Balanced view: civil disobedience is justified only against serious injustice, after lawful means have failed, and when it is non-violent, public and ready to accept the penalty. In India, Article 19 guarantees freedom of speech, peaceful assembly without arms and association, subject to reasonable restrictions, so peaceful protest is lawful, but deliberate law-breaking remains punishable and the courts decide each case.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

CONCLUSION

Civil disobedience is not an enemy of the rule of law but a conscientious appeal from the law as it is to the law as it ought to be. Used rarely, peacefully and against grave injustice, it can strengthen democracy; used carelessly, it can weaken respect for all laws.

Q.6 · Unit 4 10 marks · ≈ 600–700 words

What is totalitarianism? Explain its main features and distinguish it from democracy.

INTRODUCTION

Totalitarianism is a form of rule in which the state tries to control not only politics but the whole of social, economic, cultural and even private life. The word was first used in the 1920s in Italy by critics of Mussolini, and Mussolini himself used it proudly in the formula "everything within the state, nothing outside the state, nothing against the state". The classic examples are Nazi Germany under Hitler, Fascist Italy and Stalin's Soviet Union.

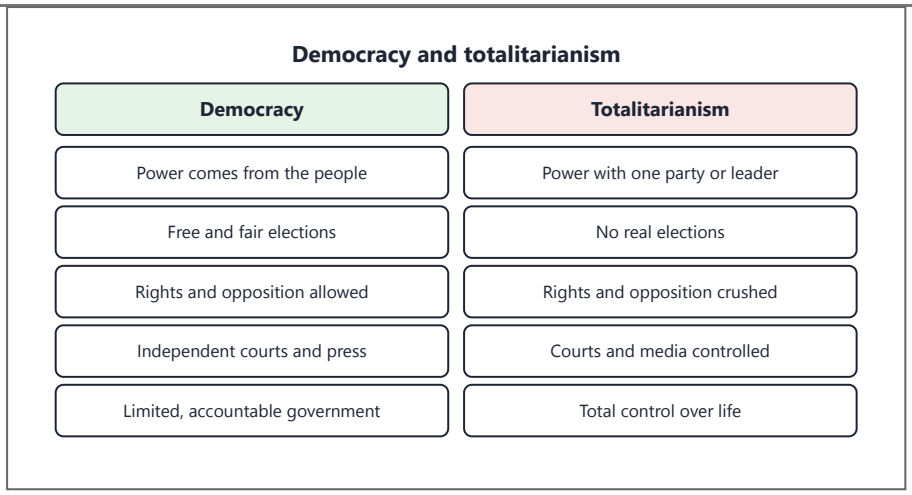
MEANING

A totalitarian system is one where a single party and a single leader hold unlimited power, an official ideology is imposed on all, and individuals exist to serve the state. The individual has no sphere of private freedom. Hannah Arendt's *The Origins of Totalitarianism* (1951) and the work of Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski are the standard studies.

MAIN FEATURES

1. **Single-party rule:** only one party, led by a supreme leader, is allowed. All other parties are banned and the party is merged with the state.
2. **Official ideology:** one doctrine, such as Nazism, Fascism or Marxism-Leninism, explains everything and is taught to all through schools and media.
3. **Dictator and cult of personality:** the leader is shown as infallible. Slogans such as "the Führer is always right" were common.
4. **Control of the economy:** the state directs production and labour, either by ownership or by strict control.
5. **Control of media and education:** newspapers, radio, cinema and schools are used for propaganda, and independent thought is not tolerated.
6. **Secret police and terror:** the Gestapo in Germany and the NKVD in the Soviet Union spread fear through arrests, camps and executions.
7. **No rights or opposition:** freedom of speech, assembly and association is suppressed, and courts are not independent.
8. **Militarism and expansion:** war and national glory are glorified, and mass mobilisation is common.
9. **Destruction of civil society:** clubs, unions and churches are controlled or dissolved so that nothing stands between the individual and the state.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Democracy compared with totalitarianism

TOTALITARIANISM AND DEMOCRACY

Basis	Democracy	Totalitarianism
Source of power	The people	Leader or party
Parties	Many; opposition allowed	One party only
Elections	Free and fair	Absent or fake
Rights	Guaranteed	Suppressed
Judiciary and press	Independent	Controlled
Individual	An end in himself	A tool of the state
Change of government	Peaceful, by vote	By coup or death
Ideology	Plural	Single official ideology
Government	Limited, accountable	Unlimited, unaccountable

TOTALITARIANISM AND AUTHORITARIANISM

Authoritarian rulers also deny democracy, but they usually leave society, religion and private life alone. Totalitarian rulers try to control and remake all aspects of life and to mobilise every citizen with an ideology.

CRITICISM

- It destroys liberty, dignity and human rights.
- It depends on fear, not consent, and so it lacks real legitimacy.
- There is no peaceful method for removing a bad ruler.
- It suppresses creativity, science and art.
- It often led to war and mass killing, as in the Second World War and the Holocaust.

WHY IT AROSE

Humiliation after the First World War, economic crisis such as the Great Depression, fear of communism, extreme nationalism and weak democratic institutions helped totalitarian movements to rise in Italy and Germany.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

CONCLUSION

Totalitarianism is the opposite of democratic government. It treats the individual as a means and gives the ruler unchecked power. The collapse of Nazi and Fascist regimes in 1945 and the end of the Soviet system in 1991 show that regimes depending on fear are unstable. Democracy, with its rights, free press and independent courts, remains the safeguard against any return of such rule.

Q.6 (OR) · Unit 4 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the theories of representation and compare the majority system with proportional representation.

INTRODUCTION

In a modern state with millions of people, all citizens cannot meet together to make laws as in the ancient Greek city-states. Democracy therefore works through **representation**: the people choose a small number of persons to speak and decide on their behalf. Two questions arise: whom should representatives represent and how should they be elected? The first is answered by the theories of representation, and the second by the electoral system.

MEANING

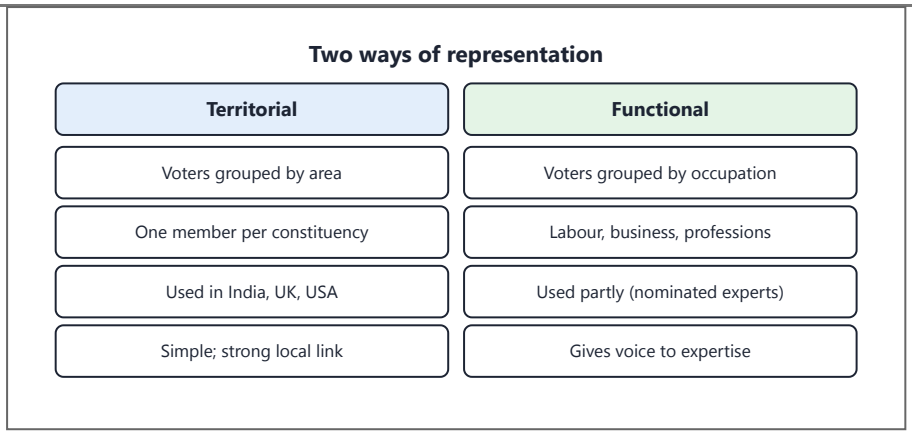
Representation means that a few elected persons act for the many. Edmund Burke, in his speech to the electors of Bristol (1774), held that a representative owes the voters his judgment and should not be a mere delegate.

THEORIES OF REPRESENTATION

1. **Trustee (Burkean) theory:** the representative is a wise trustee who uses his own judgment for the national interest, even against the wishes of his constituents.
2. **Delegate (mandate) theory:** the representative is an agent who carries out the instructions of his voters, as in the idea of the party manifesto and the mandate.
3. **Territorial representation:** voters are grouped by geographical area, and each constituency elects its own member. It is used in India, the UK and the USA.
4. **Functional (occupational) representation:** voters are grouped by occupation, such as labour, industry and the professions, so that each interest gets a voice. Guild socialists and G. D. H. Cole supported it. In India, the nomination of experts to the Rajya Sabha reflects it only in a limited sense.
5. **Marxist view:** representation in a capitalist state mainly serves the ruling class.
6. **Descriptive and group representation:** the legislature should reflect the population, so seats are reserved for women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India.

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



Territorial and functional representation

ELECTORAL SYSTEMS

A. Majority system.

- *Single-member plurality (first-past-the-post):* the candidate with the most votes in a constituency wins, even without a majority. It is used for the Lok Sabha.
- *Second ballot:* if no one gets an absolute majority, a second round is held between the top candidates, as in France.

B. Proportional representation (PR). Seats are divided in proportion to votes. In the *single transferable vote* (Hare system) voters rank candidates in multi-member constituencies. In India, this system, in its form of a preferential vote, is used for the President, Vice-President, Rajya Sabha and the Legislative Council elections. The *list system* is used in countries such as Israel and the Netherlands.

MERITS AND DEMERITS OF THE MAJORITY SYSTEM

Merits	Demerits
Simple and easy to understand	Winner may get less than half the votes
Direct link with the constituency	Votes for losing candidates are wasted
Gives stable, single-party government	Small parties and minorities under-represented
Encourages a two-party system	Seats do not match vote share

MERITS AND DEMERITS OF PROPORTIONAL REPRESENTATION

Merits	Demerits
Every vote counts	Complex counting
Minorities and small parties get seats	Encourages many parties and coalitions
Seats match vote share	Weak local link of the member
More democratic and fair	Government may be unstable

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

COMPARISON

Basis	Majority system	Proportional representation
Constituency	Single-member	Multi-member
Result	Winner takes all	Seats by share of votes
Party system	Favours two parties	Favours many parties
Government	Usually stable	Often coalition
Example	Lok Sabha, UK	Israel, Netherlands

INDIAN POSITION

The Constituent Assembly rejected PR for the Lok Sabha because of India's size, low literacy at the time and fear that many small parties would cause instability. Plurality voting is used for the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas, while indirect elections use the single transferable vote.

CONCLUSION

No electoral system is perfect. The majority system gives stability and local accountability but may be unfair to minorities, while PR is fairer but may cause instability. Many countries therefore adopt mixed systems, as in Germany. Whatever the system, a good theory of representation requires that elected members remain accountable to the people and protect the interests of all sections.

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

भाग – II : हिन्दी माध्यम – आदर्श उत्तर

प्रत्येक उत्तर अंक-भार के अनुसार लिखा गया है — ढाँचा सीखें, फिर अपने शब्दों में लिखें।

खण्ड – अ · प्रश्न 1 : उत्तर कुंजी

क्र.	उत्तर	सही विकल्प	स्पष्टीकरण
1	(a)	नगर-राज्य	'पोलिस' यूनान का छोटा स्वशासित नगर-राज्य था, जिसका अध्ययन अरस्तू ने किया; इसलिए राजनीति 'पोलिस' के कार्यों का अध्ययन है।
2	(b)	आदर्शात्मक (मानकीय) सिद्धांत	आदर्शात्मक सिद्धांत राज्य और राजनीति को आदर्शों व मूल्यों की कसौटी पर परखता है; अनुभवमूलक सिद्धांत जो वास्तव में है उसका वर्णन व व्याख्या करता है।
3	(d)	राजनीतिक दल	चार अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, भू-भाग, सरकार और संप्रभुता। राजनीतिक दल लोकतंत्र में महत्वपूर्ण हैं, पर राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं।
4	(c)	संप्रभु राष्ट्र-राज्यों की आधुनिक व्यवस्था	इन संधियों ने तीस वर्षीय युद्ध समाप्त किया और निश्चित भू-भाग वाले संप्रभु राज्यों का सिद्धांत स्थापित किया, जो आधुनिक राज्य-व्यवस्था का आधार है।
5	(a)	जन्म या वंश	'नैशियो' का अर्थ जन्म या वंश है; राष्ट्र पहले समान वंश का समूह था और अब साझा इतिहास, संस्कृति व भावना से बँधा जनसमूह है।
6	(b)	ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971)	रॉल्स ने 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' (1971) में निष्पक्षता के रूप में न्याय, मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
7	(c)	राजनीतिक समानता	धन, जाति या लिंग का भेद किए बिना प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान मताधिकार राजनीतिक समानता है।
8	(d)	रूसो	रूसो की 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' (1762) संप्रभुता को जनता में मानती है और उसे सामान्य इच्छा से जोड़ती है।
9	(a)	न्यायिक पुनर्विलोकन	न्यायिक पुनर्विलोकन से न्यायपालिका कानूनों व कार्यपालिका के कार्यों को संविधान की कसौटी पर परखकर उल्लंघन करने वालों को निरस्त कर सकती है।
10	(b)	एकमात्र दल जो जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करता है	सर्वाधिकारवादी राज्य में एक शासक दल, एक विचारधारा और राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया व निजी जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

खण्ड – अ · प्रश्न 2 : लघु उत्तर

प्रश्न 2(a) — 4 अंक · शब्द-सीमा ≈ 100–120 शब्द

राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख कार्य बताइए।

राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो बताते हैं कि राजनीतिक जीवन कैसे संगठित है और कैसे संगठित होना चाहिए। इसमें राज्य, शक्ति, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अध्ययन होता है।

राजनीतिक सिद्धांत के कार्य

- **व्याख्या:** यह बताता है कि राजनीतिक संस्थाएँ क्यों बनती हैं और कैसे काम करती हैं।
- **मूल्यांकन:** यह कानूनों और संस्थाओं को न्याय व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर परखता है।
- **निर्देशन:** यह सुझाव देता है कि राजनीतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **स्पष्टीकरण:** यह अवधारणाओं को सटीक अर्थ देता है, जिससे बहस स्पष्ट रहती है।
- **मार्गदर्शन:** यह नागरिकों, नेताओं और सुधारकों को कर्म की दिशा देता है।

इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों को मूल्यों से जोड़ता है; इसके बिना राजनीति केवल सत्ता का संघर्ष रह जाएगी।

प्रश्न 2(b) — 4 अंक · शब्द-सीमा ≈ 100–120 शब्द

राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।

राज्य जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार और संप्रभुता वाला विधिक-राजनीतिक संगठन है। **राष्ट्र** उन लोगों का समुदाय है जो साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा या भावना से एकता अनुभव करते हैं और स्वयं को एक जन मानते हैं।

आधार	राष्ट्र	राज्य
प्रकृति	सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक एकता	विधिक व राजनीतिक संगठन
अनिवार्य तत्व	एकता की भावना	भू-भाग व संप्रभुता
भू-भाग	निश्चित भू-भाग आवश्यक नहीं (जैसे कुर्द)	निश्चित भू-भाग अनिवार्य
संप्रभुता	आवश्यक नहीं	अनिवार्य
सदस्यता	भावना पर आधारित	नागरिकता पर आधारित

एक राष्ट्र कई राज्यों में बँट सकता है (कोरिया) और एक राज्य में कई समुदाय हो सकते हैं (भारत); जहाँ दोनों लगभग मेल खाते हैं, उसे राष्ट्र-राज्य कहते हैं, जैसे जापान।

प्रश्न 2(c) — 4 अंक · शब्द-सीमा ≈ 100–120 शब्द

जॉन रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांत बताइए।

जॉन रॉल्स ने 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' (1971) में कहा कि न्याय के सिद्धांत वे हैं जिन्हें स्वतंत्र और विवेकशील लोग एक काल्पनिक **मूल स्थिति** में, **अज्ञानता के पर्दे** के पीछे चुनेंगे, जहाँ किसी को अपना वर्ग, प्रतिभा या धर्म ज्ञात नहीं होता।

दो सिद्धांत

1. **समान मूल स्वतंत्रताएँ:** प्रत्येक व्यक्ति को सबके लिए समान स्वतंत्रताओं के अनुरूप व्यापकतम मूल स्वतंत्रताओं (बोलने, मत देने, अंतःकरण) का समान अधिकार है।
2. **सामाजिक व आर्थिक असमानताएँ** तभी उचित हैं जब (क) वे **सबसे वंचित वर्ग** के सर्वाधिक हित में हों, जिसे **भेद सिद्धांत** कहा जाता है, और (ख) पद व अवसर **अवसर की न्यायपूर्ण समानता** के साथ सबके लिए खुले हों।

पहला सिद्धांत दूसरे से पहले आता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 2(d) 4 अंक · शब्द-सीमा ≈ 100–120 शब्द

रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा समझाइए।

रूसो ने 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' (1762) में कहा कि राज्य की वैध सत्ता **सामान्य इच्छा** पर टिकी है, जो सार्वजनिक हित के लिए समुदाय की इच्छा है।

अर्थ व विशेषताएँ

- सामान्य इच्छा **सबकी इच्छा** नहीं है, जो स्वार्थी निजी इच्छाओं का योग मात्र है; यह वह है जो हर नागरिक समुदाय के सदस्य के रूप में चाहता है।
- यह सदा **सही** (सार्वजनिक हित-निर्देशित), **अविभाज्य** और **अहस्तांतरणीय** है।
- संप्रभुता जनता में निहित है; सरकार केवल उसकी एजेंट है।
- जो पालन नहीं करता उसे "स्वतंत्र होने के लिए विवश" किया जा सकता है, क्योंकि कानून बनाने में वह स्वयं भागीदार है।

आलोचकों के अनुसार इससे बहुमत का अत्याचार उचित ठहराया जा सकता है, फिर भी यह लोकप्रिय संप्रभुता और आधुनिक लोकतंत्र की नींव है।

प्रश्न 2(e) 4 अंक · शब्द-सीमा ≈ 100–120 शब्द

लचीले और कठोर संविधान में अंतर कीजिए।

लचीला संविधान साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से बदला जा सकता है, जबकि **कठोर संविधान** में संशोधन के लिए विशेष और कठिन प्रक्रिया आवश्यक होती है।

आधार	लचीला संविधान	कठोर संविधान
संशोधन	साधारण कानून जैसी प्रक्रिया	विशेष बहुमत, अनुसमर्थन या जनमत संग्रह
अनुकूलनशीलता	समय के साथ शीघ्र बदलता है	धीरे बदलता है
स्थायित्व	कम स्थायी, जल्दबाज़ी में बदलाव संभव	अधिक स्थायी व सुरक्षित
अधिकारों की सुरक्षा	कमज़ोर	अधिक मज़बूत
उदाहरण	ब्रिटेन	संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत ने **मिश्रित** मार्ग अपनाया है: संविधान के कुछ भाग साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ में आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से भी बदले जा सकते हैं (अनुच्छेद 368)। अच्छा संविधान स्थायित्व और अनुकूलनशीलता में संतुलन रखता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

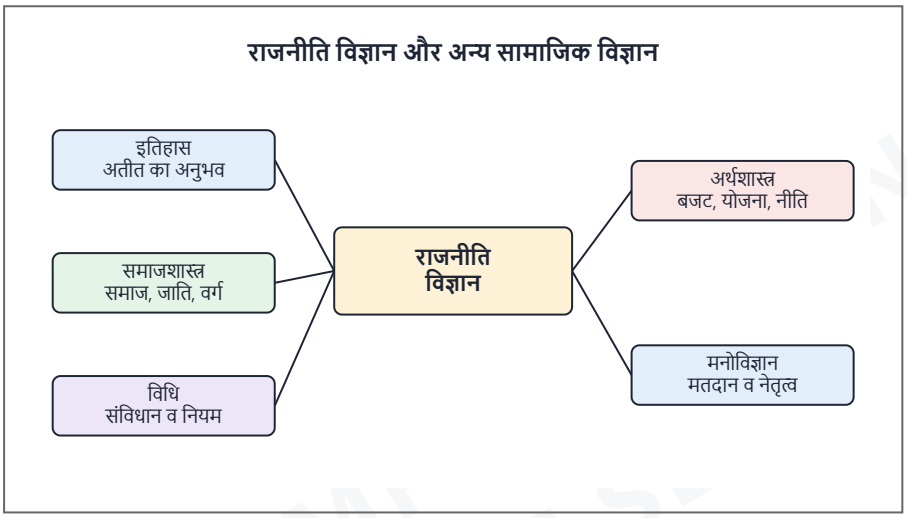
खण्ड – ब · दीर्घ उत्तर

प्रश्न 3 · इकाई 1 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

राजनीति विज्ञान का इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और विधि से संबंध स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना

राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, शक्ति और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। परंतु मानव जीवन अलग-अलग खानों में बँटा नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी घटनाएँ आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे से सहायता लेते हैं। जो विद्यार्थी पड़ोसी विषयों को छोड़ देता है, वह चित्र का केवल एक हिस्सा देख पाता है। प्रमुख विषयों से संबंध नीचे स्पष्ट किया गया है।



राजनीति विज्ञान और उसके निकटवर्ती सामाजिक विज्ञान

1. राजनीति विज्ञान और इतिहास

इतिहास राज्यों, शासकों, युद्धों और क्रांतियों के अतीत को दर्ज करता है, जबकि राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। जे. आर. सीले का कथन प्रसिद्ध है: *"इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की जड़ नहीं है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का फल नहीं है।"*

- इतिहास कच्ची सामग्री देता है: फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐसे तथ्य हैं जिनका अध्ययन राजनीतिक विचारक करते हैं।
- राजनीति विज्ञान उस सामग्री का विश्लेषण करके सबक निकालता है और संप्रभुता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र जैसी अवधारणाएँ बनाता है।
- संसद या संघीय व्यवस्था जैसी संस्थाओं को उनके विकास को जाने बिना नहीं समझा जा सकता।

2. राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र

प्राचीन विचारक इस विषय को "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" कहते थे; एडम स्मिथ की *वेल्थ ऑफ़ नेशंस* (1776) इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। आज भी दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।

- आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को आकार देती है: धनी वर्ग और उद्योग कानून-निर्माण, चंदे और नीति को प्रभावित करते हैं।
- राजनीतिक निर्णय अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं: बजट, कर, सब्सिडी और योजना सरकारें तय करती हैं। भारत के 1991 के उदारीकरण सुधार आर्थिक प्रभाव वाला राजनीतिक निर्णय थे।
- चुनाव प्रायः महँगाई, रोज़गार और कल्याण जैसे आर्थिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

3. राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र

समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है: उसके समूह, रीति-रिवाज, परिवार, जाति और वर्ग। राज्य समाज की केवल एक संस्था है, इसलिए राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र पर निर्भर है।

- सामाजिक संरचना राजनीति को प्रभावित करती है: भारत में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र मतदान तथा दल-निर्माण को प्रभावित करते हैं।
- राजनीति समाज को बदलती है: अस्पृश्यता समाप्त करने या महिला अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून सामाजिक जीवन बदलते हैं।
- दबाव समूह, राजनीतिक समाजीकरण और सामाजिक आंदोलन जैसे विषय दोनों के अध्ययन में आते हैं।

4. राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान व्यक्ति के मन और व्यवहार का अध्ययन करता है। ग्राहम वालास की *ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स* (1908) ने तर्क दिया कि मानवीय प्रेरणाओं को समझे बिना राजनीति नहीं समझी जा सकती, और हेरोल्ड लासवेल की *साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स* (1930) ने राजनीतिक नेताओं पर मनोविज्ञान लागू किया।

- मतदान व्यवहार, जनमत, प्रचार और नेतृत्व शैली को दृष्टिकोण, भावनाओं और धारणाओं से समझाया जाता है।
- राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम इसी संबंध से विकसित हुआ।

5. राजनीति विज्ञान और विधि

विधि राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों का समूह है, इसलिए दोनों बहुत निकट हैं।

- संविधान, जो राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है, सर्वोच्च कानून भी है।
- राजनीति विज्ञान पूछता है कि कानूनों का पालन क्यों हो और उन्हें न्यायपूर्ण क्या बनाता है; विधि बताती है कि नियम क्या हैं और न्यायालय उन्हें कैसे लागू करते हैं।
- संप्रभुता, अधिकार, विधि का शासन (भारत में अनुच्छेद 14) और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी अवधारणाएँ दोनों में साझा हैं।
- फिर भी अंतर है: विधि बताती है कि नियम *क्या है*, जबकि राजनीति विज्ञान यह भी पूछता है कि नियम *कैसा होना चाहिए*।

एक नज़र में तुलना

विषय	अध्ययन का केंद्र	राजनीति विज्ञान से संबंध
इतिहास	अतीत	तथ्य और सबक देता है
अर्थशास्त्र	धन और उत्पादन	नीति, बजट, वर्ग-हित
समाजशास्त्र	समाज और समूह	राजनीति का सामाजिक आधार
मनोविज्ञान	मन और व्यवहार	मतदान, जनमत, नेतृत्व
विधि	नियम और न्यायालय	संविधान, अधिकार, न्याय

निष्कर्ष

राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों के संगम पर खड़ा है। यह इतिहास से तथ्य, अर्थशास्त्र से प्रतिमान, समाजशास्त्र से सामाजिक संदर्भ, मनोविज्ञान से व्यवहारगत समझ और विधि से नियम लेता है, और बदले में उन्हें राज्य और शक्ति की समझ देता है। इसलिए आधुनिक विद्यार्थी को अंतर्विषयी दृष्टि चाहिए, और इसी कारण अब यह विषय तुलनात्मक तथा व्यवहारवादी पद्धतियों से पढ़ा जाता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 3 (अथवा) • इकाई 1 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? पक्ष और विपक्ष के तर्कों सहित चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना

राजनीति विज्ञान को "विज्ञान" कहा जाए या नहीं, यह पुरानी बहस है। भौतिकी जैसे प्राकृतिक विज्ञान की पहचान क्रमबद्ध अवलोकन, प्रयोग, सटीक नियम और पूर्वानुमान की क्षमता से होती है। प्रश्न यह है कि राज्य और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इन कसौटियों पर कितना खरा उतरता है। अरस्तू ने राजनीति को "सर्वोच्च विज्ञान" कहा था क्योंकि वह अन्य सभी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करती है, परंतु आधुनिक लेखक दो पक्षों में बँटे हैं।

क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
ज्ञान का क्रमबद्ध भंडार	प्रयोगशाला प्रयोग संभव नहीं
अवलोकन व तुलना	मानव इच्छा अप्रत्याशित
कारण-परिणाम संबंध (दुवर्जे नियम)	मूल्य व पूर्वाग्रह का प्रभाव
सर्वेक्षण व व्यवहारवादी पद्धतियाँ	सार्वभौमिक सटीक नियम नहीं
कुछ पूर्वानुमान (जनमत सर्वेक्षण)	मूल अवधारणाएँ विवादित

क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है?

"विज्ञान" का अर्थ

कठोर अर्थ में विज्ञान ऐसा ज्ञान-समूह है जो (i) क्रमबद्ध और संगठित हो, (ii) अवलोकन और प्रमाण पर आधारित हो, (iii) प्रयोग से परखा गया हो, (iv) सार्वभौमिक कारण-परिणाम नियम खोज सके और (v) भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर सके। इन कसौटियों पर विषय को दो तरह से परखा जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- **क्रमबद्ध ज्ञान:** राजनीति विज्ञान के पास राज्य, सरकार, अधिकार और राजनीतिक दलों पर संगठित अवधारणाओं, तथ्यों और सिद्धांतों का भंडार है।
- **अवलोकन और तुलना:** विद्वान संविधानों, चुनावों और संस्थाओं से तथ्य एकत्र करते हैं और तुलनात्मक पद्धति से अनेक देशों की तुलना करते हैं।
- **कारण-परिणाम संबंध:** कुछ नियमितताएँ देखी गई हैं। मॉरिस दुवर्जे का अवलोकन (प्रायः दुवर्जे का नियम कहा जाता है) बताता है कि एकल-सदस्यीय बहुमत प्रणाली दो-दलीय व्यवस्था को जन्म देती है।
- **व्यवहारवादी क्रांति:** द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाहल जैसे लेखकों ने मतदान, जनमत और निर्णय-निर्माण के अध्ययन में सर्वेक्षण, सांख्यिकी और साक्षात्कार का प्रयोग शुरू किया।
- **पूर्वानुमान:** जनमत सर्वेक्षण और एग्ज़िट पोल चुनाव परिणामों का अनुमान लगाते हैं, तथा राजनीतिक जोखिम विश्लेषक अस्थिरता का पूर्वानुमान करते हैं।
- **स्व-सुधार वाली पद्धति:** सिद्धांतों को नए प्रमाणों से परखा और संशोधित किया जाता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

विपक्ष में तर्क

- **प्रयोगशाला प्रयोग नहीं:** रसायनशास्त्री जैसे अभिक्रिया दोहराता है, वैसे राजनीति वैज्ञानिक क्रांति या चुनाव को नियंत्रित स्थितियों में दोहरा नहीं सकता।
- **मानव इच्छा अप्रत्याशित:** लोगों में स्वतंत्र इच्छा होती है और वे मन बदल लेते हैं, इसलिए एक ही कारण से एक-सा परिणाम नहीं मिलता। चुनावी अनुमान कभी-कभी गलत हो जाते हैं।
- **मूल्य और पूर्वाग्रह:** शोधकर्ता भी एक नागरिक है जिसकी अपनी मान्यताएँ होती हैं, इसलिए पूर्ण वस्तुनिष्ठता कठिन है। स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे शब्दों की व्याख्या विचारक अलग-अलग करते हैं।
- **सार्वभौमिक नियम नहीं:** अधिकांश निष्कर्ष किसी विशेष समय और स्थान पर ही लागू होते हैं; न्यूटन के नियमों जैसे सटीक नियम नहीं हैं।
- **विवादित अवधारणाएँ:** "शक्ति" या "राज्य" जैसे मूल शब्दों की भी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।
- **बहुत अधिक चर:** राजनीति अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इतिहास और संयोग से एक साथ प्रभावित होती है, इसलिए कारणों को अलग करना कठिन है।

तुलना

विज्ञान की कसौटी	प्राकृतिक विज्ञान	राजनीति विज्ञान
प्रयोग	प्रयोगशाला में संभव	बहुत कम संभव
नियम	सार्वभौमिक व सटीक	प्रवृत्तियाँ, सटीक नहीं
पूर्वानुमान	प्रायः सही	सीमित और अनिश्चित
मूल्य-मुक्त	काफी हद तक हाँ	कठिन
विषय-वस्तु	पदार्थ और ऊर्जा	विचारशील मनुष्य

मूल्यांकन

दोनों चरम उत्तर असंतोषजनक हैं। यदि "विज्ञान" का अर्थ केवल भौतिकी की सटीक पद्धति है, तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। परंतु यदि विज्ञान का अर्थ ज्ञान की क्रमबद्ध, प्रमाण-आधारित और स्व-सुधारी खोज है, तो यह उसमें आता है। अनेक आधुनिक विद्वानों का संतुलित मत है कि यह एक **सामाजिक विज्ञान** या "अपूर्ण विज्ञान" है: यह वैज्ञानिक *पद्धति* और भावना का पालन करता है, किंतु उतनी निश्चितता नहीं पा सकता क्योंकि इसका विषय बदलता हुआ मनुष्य है। चिकित्सा और मौसम-विज्ञान भी अपूर्ण पूर्वानुमान के बावजूद विज्ञान कहे जाते हैं।

निष्कर्ष

राजनीति विज्ञान भौतिकी जैसा सटीक विज्ञान नहीं है, फिर भी यह मात्र राय से अधिक है। यह अवलोकन, तुलना, सांख्यिकी और सिद्धांत के सहारे विश्वसनीय किंतु सीमित और संभाव्य ज्ञान देता है। व्यवहारवादी और तुलनात्मक उपागमों से इसकी प्रगति दिखाती है कि यह धीरे-धीरे अधिक वैज्ञानिक हो रहा है, जबकि इसका मूल्य-पक्ष इसे दर्शन के निकट रखता है।

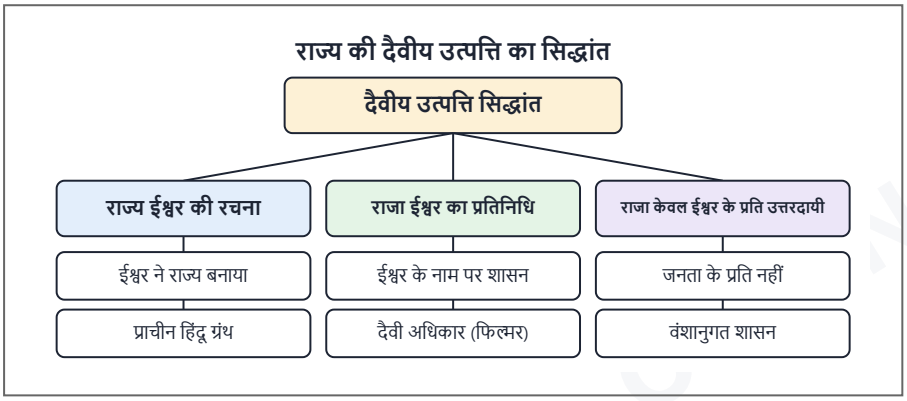
© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 4 • इकाई 2 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके गुण-दोषों की समीक्षा कीजिए।

प्रस्तावना

"राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई?" इस प्रश्न के अनेक उत्तर दिए गए हैं: दैवीय, शक्ति, सामाजिक समझौता, विकासवादी आदि। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानव की रचना नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित है और शासक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में यह सिद्धांत प्रभावी था, जब धर्म सोच और राजनीति पर हावी था।



दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत और उसके तीन रूप

सिद्धांत की मुख्य बातें

- राज्य एक दैवीय संस्था है, जिसे ईश्वर ने मानव-कल्याण के लिए बनाया।
- राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या अवतार है और ईश्वर की इच्छा से शासन करता है।
- राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं।
- राजा की आज्ञा मानना धार्मिक कर्तव्य है और अवज्ञा पाप है।

सिद्धांत के रूप

1. **धर्मतंत्र (थियोक्रेसी):** स्वयं ईश्वर प्रत्यक्ष शासक है और पुजारी या पैगंबर उसकी ओर से बोलते हैं। पैगंबरों के अधीन यहूदी राज्य और मध्यकालीन पोप के दावे इसके उदाहरण हैं। कुछ प्राचीन समाजों में शासक को देवता माना जाता था।
2. **राजाओं का दैवी अधिकार:** ईश्वर राजवंश को चुनता है और शासन का अधिकार वंश-परंपरा से मिलता है। सत्रहवीं सदी के इंग्लैंड में जेम्स प्रथम और सर रॉबर्ट फिल्मर (*पैट्रियार्का*) ने तर्क दिया कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं।
3. **दैवी स्वीकृति:** राज्य मानव की रचना है परंतु ईश्वर द्वारा अनुमोदित है, इसलिए उसकी सत्ता पवित्र है। "सत्ता ईश्वर से आती है" वाला ईसाई कथन और कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों के विचार, जैसे राजा का दैवी विधान के अंतर्गत रक्षक होना, यहाँ रखे जाते हैं।

इतिहास से उदाहरण

- प्राचीन मिस्र में फ़िरौन को देवता माना जाता था और जापान में सम्राट को लंबे समय तक दैवीय माना गया।
- मध्यकालीन यूरोप में पोप और चर्च ने यह तय करने में ऊँची भूमिका का दावा किया कि किसका राज्याभिषेक हो।
- प्राचीन भारत में महाभारत जैसे ग्रंथ राजा को दैवी गुणों से युक्त बताते हैं, परंतु अनेक भारतीय विचारकों ने राजसत्ता की सीमा के रूप में *धर्म* पर भी बल दिया।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

गुण

- इसने लोगों से सत्ता का पालन कराया, जिससे आरंभिक समाजों में व्यवस्था और अनुशासन आया।
- इसने शासकों को स्थिरता दी और विद्रोह का भय घटाया।
- धर्म ने जनता और शासक को जोड़ा, जिससे निष्ठा और एकता बनी।
- इसने सत्ता के नैतिक और आध्यात्मिक आधार को सही रूप में रेखांकित किया।

आलोचना

- **अवैज्ञानिक:** ईश्वर द्वारा किसी राज्य के निर्माण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है; राज्य रक्त-संबंध, धर्म, बल और आवश्यकता से विकसित हुए।
- **निरंकुशता का समर्थन:** इसने राजाओं को उत्तरदायित्व के बिना शासन करने दिया और अत्याचार का बचाव करने में प्रयुक्त हुआ।
- **लोकतंत्र विरोधी:** यह जनता की संप्रभुता और शासकों से प्रश्न पूछने के अधिकार को नकारता है।
- **अनेक धर्म, अनेक राज्य:** यह नहीं समझा पाता कि अलग-अलग देवता या धर्म अलग, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी राज्यों का समर्थन क्यों करते हैं।
- **आधुनिक युग में अनुचित:** शासक के कानून से ऊपर होने की धारणा को विधि के शासन और संविधानवाद ने नकार दिया है।
- **राजनीति और धर्म का मिश्रण:** धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म और राजनीतिक सत्ता अलग रखे जाते हैं।

सिद्धांत का पतन

सुधार आंदोलन, इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तथा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद यह सिद्धांत कमज़ोर पड़ गया। सहमति और प्राकृतिक अधिकारों के पक्षधर लॉक जैसे विचारकों ने दैवी सत्ता के स्थान पर जन-सहमति को रखा।

अन्य सिद्धांतों से तुलना

सिद्धांत	राज्य का स्रोत	आज की स्थिति
दैवीय उत्पत्ति	ईश्वर की इच्छा	इतिहास के रूप में अस्वीकृत
शक्ति सिद्धांत	विजय और बल	आंशिक सत्य
सामाजिक समझौता	जनता की सहमति	लोकतंत्र का आधार
विकासवादी	क्रमिक विकास	सर्वाधिक स्वीकृत

निष्कर्ष

राज्य के आरंभ की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है, और जब इसने निरंकुश शासन को उचित ठहराया तब यह हानिकारक रहा। इसका स्थायी योगदान यह विचार है कि राजनीतिक सत्ता को नैतिक समर्थन चाहिए और शक्ति को किसी उच्च उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। आधुनिक राजनीतिक चिंतन विकासवादी मत को स्वीकार करता है, जिसमें राज्य सामाजिक आवश्यकताओं से विकसित होता है और शासितों की सहमति पर टिका होता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 4 (अथवा) • इकाई 2 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

राष्ट्रवाद क्या है? इसके तत्त्वों, प्रकारों, गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना

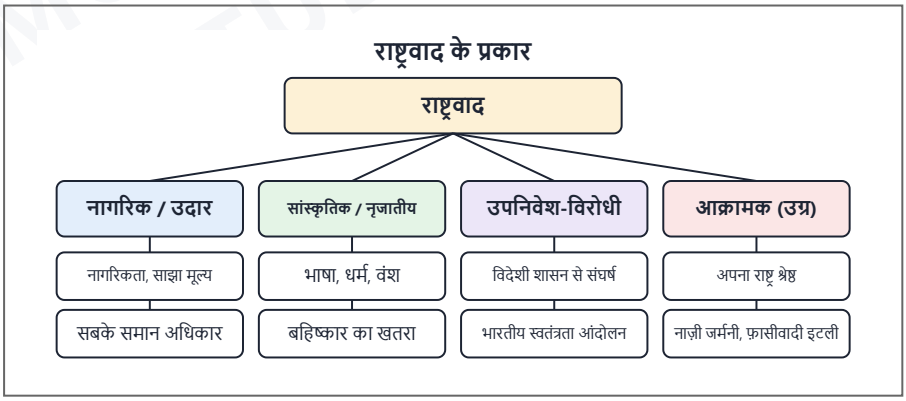
राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा और लगाव की भावना है, साथ ही यह विश्वास कि राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार है। यह आधुनिक युग की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक है। इसने उन्नीसवीं सदी में इटली और जर्मनी को एक किया, एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलनों को ऊर्जा दी, और तानाशाहों ने इसका दुरुपयोग भी किया। यह "राष्ट्र" के विचार पर टिका है, अर्थात ऐसे लोग जो अपने को एक साथ जुड़ा हुआ मानते हैं।

अर्थ

राष्ट्रवाद ऐसी राजनीतिक और सांस्कृतिक भावना है जिसमें लोग संकीर्ण स्थानीय निष्ठाओं के ऊपर अपने राष्ट्र के हित, एकता और सम्मान को रखते हैं। राष्ट्र-राज्य, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र का अपना संप्रभु राज्य हो, इसका राजनीतिक लक्ष्य है। यह शब्द लैटिन *नातियो* से बना है, जिसका अर्थ जन्म या नस्ल है।

राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्त्व

- **साझा इतिहास और स्मृतियाँ:** साझा संघर्ष और नायक, जैसे भारत में 1857 का विद्रोह या नमक सत्याग्रह, अपनत्व को मज़बूत करते हैं।
- **साझा संस्कृति, भाषा और धर्म:** ये "हम" की भावना देते हैं, पर सहायक हैं, अनिवार्य नहीं। स्विट्ज़रलैंड में अनेक भाषाएँ हैं फिर भी एक राष्ट्र है।
- **साझा भू-भाग:** मातृभूमि से लगाव।
- **साझा राजनीतिक आकांक्षाएँ:** स्वतंत्र होने और स्वयं शासन करने की इच्छा।
- **साझा आर्थिक हित और साझा शत्रु:** विदेशी शासन प्रायः लोगों को एक करता है।
- **साथ रहने की इच्छा:** अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र को "रोज़ का जनमत-संग्रह" कहा, जो साथ रहने की इच्छा पर टिका है।



राष्ट्रवाद के प्रकार

राष्ट्रवाद के प्रकार

1. **नागरिक या उदार राष्ट्रवाद:** सदस्यता वंश पर नहीं, नागरिकता और साझा राजनीतिक मूल्यों पर निर्भर है। सबको समान अधिकार देने वाला भारतीय संविधान इसी विचार पर चलता है। इतालवी विचारक मैज़िनी का मत था कि प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र हो और राष्ट्र आपस में सहयोग करें।
2. **सांस्कृतिक या नृजातीय राष्ट्रवाद:** राष्ट्र की पहचान साझा भाषा, धर्म या वंश से होती है। यह विरासत बचा सकता है पर अल्पसंख्यकों को बाहर कर सकता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

3. **उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद:** उपनिवेशित लोगों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, जैसे भारत, अल्जीरिया और वियतनाम में।
4. **आक्रामक या उग्र राष्ट्रवाद:** राष्ट्र को श्रेष्ठ माना जाता है और विस्तार को उचित ठहराया जाता है। इससे नाज़ी जर्मनी और फ़ासीवादी इटली बने और द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ।

गुण

- यह भिन्न समूहों को जोड़ता है और सामाजिक एकजुटता तथा देशभक्ति पैदा करता है।
- इसने स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया और औपनिवेशिक साम्राज्यों को समाप्त किया।
- यह नागरिक गौरव, अनुशासन और देश के लिए त्याग की भावना बनाता है।
- यह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है, जैसे राष्ट्रीय भाषा और स्वदेशी उद्योग का प्रयोग।
- यह राष्ट्र-राज्य और लोकतंत्र को वैधता देता है, क्योंकि यह जनता की संप्रभुता के विचार पर टिका है।

दोष

- **आक्रामक राष्ट्रवाद युद्ध की ओर ले जाता है,** जैसे दोनों विश्वयुद्धों में।
- **अल्पसंख्यकों का बहिष्कार:** राष्ट्र की संकीर्ण परिभाषा "बाहरी" लोगों, प्रवासियों या अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा पैदा कर सकती है।
- **नस्लीय श्रेष्ठता:** यह पूर्वाग्रह और हिंसा को जन्म दे सकता है, जैसे नाज़ी सिद्धांत में।
- **विश्व-सहयोग में बाधा:** अति-राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयता का और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के वैश्विक समाधान का विरोध करता है।
- **नेताओं द्वारा दुरुपयोग:** राजनेता राष्ट्रीय भावना का प्रयोग अपनी विफलताएँ छिपाने और असहमति दबाने के लिए कर सकते हैं।
- **अलगाववाद:** जब समूह अपना अलग राष्ट्र माँगते हैं तो यह बहु-जातीय राज्यों को तोड़ सकता है।

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विकसित हुआ और काफी हद तक समावेशी रहा। गांधीजी ने अहिंसा और सभी समुदायों की एकता पर बल दिया, और टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद के प्रति चेताया। संविधान समान नागरिकता, मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के द्वारा नागरिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है।

राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता

आधार	राष्ट्रवाद	अंतर्राष्ट्रीयता
निष्ठा	राष्ट्र के प्रति	मानवता के प्रति
उद्देश्य	राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकता	विश्व शांति और सहयोग
खतरा	संकीर्णता, संघर्ष	पहचान का कमज़ोर होना
संतुलन	समावेशी हो तो स्वस्थ	राष्ट्रों का सम्मान करे तो स्वस्थ

निष्कर्ष

राष्ट्रवाद न पूरी तरह अच्छा है, न पूरी तरह बुरा। जब यह उदार, समावेशी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने वाला होता है, तब स्वतंत्रता, एकता और प्रगति देता है। जब यह आक्रामक और बहिष्कारी बन जाता है, तब घृणा और युद्ध का कारण बनता है। इसलिए परिपक्व राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को अन्य राष्ट्रों और मानवाधिकारों के सम्मान के साथ जोड़ता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 5 • इकाई 3 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

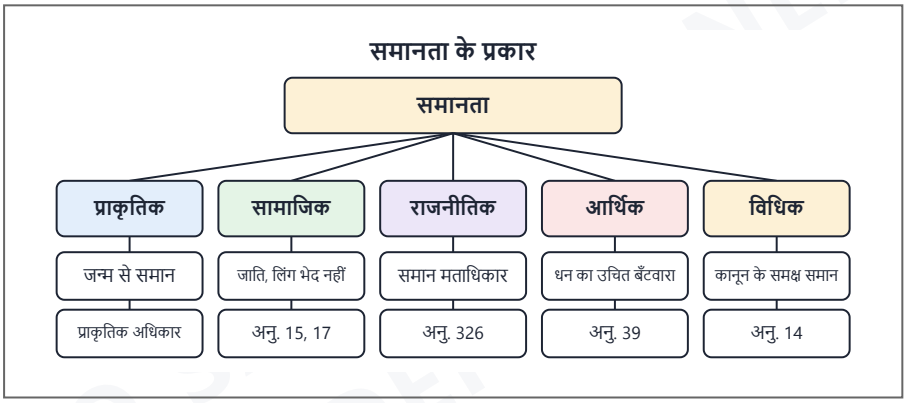
समानता क्या है? इसके विभिन्न प्रकार बताइए तथा स्वतंत्रता से इसके संबंध की चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना

समानता फ्रांसीसी क्रांति के तीन आदर्शों (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) में से एक और आधुनिक लोकतंत्र का मूल मूल्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग प्रतिभा, कद या आय में एक जैसे हों। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्यों का मूल्य समान है, वे समान सम्मान के पात्र हैं, और जन्म, जाति, लिंग, धर्म या धन के आधार पर किसी को अधिकार या अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अर्थ

समानता का अर्थ है अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों का अभाव और सबके लिए उचित तथा पर्याप्त अवसरों की उपस्थिति। हेरोल्ड लास्की ने कहा कि समानता का अर्थ पहला, विशेष विशेषाधिकार का अभाव और दूसरा, सबके लिए पर्याप्त अवसरों का खुला होना है। इसलिए प्रायः दो अर्थ अलग किए जाते हैं: **औपचारिक समानता** (सबके लिए समान अधिकार और समान कानून) और **वास्तविक समानता** (वंचित समूहों को विशेष सहायता ताकि वे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकें)।



समानता के प्रकार और संवैधानिक प्रावधान

समानता के प्रकार

1. **प्राकृतिक समानता:** सभी मनुष्य समान जन्म लेते हैं और उनके प्राकृतिक अधिकार समान हैं। रूसो और लॉक ने यह तर्क दिया, यद्यपि लोगों की योग्यता भिन्न होती है।
2. **सामाजिक समानता:** जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म-स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। भारत में अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है।
3. **नागरिक या विधिक समानता:** सभी कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। यह विधि का शासन है, जिसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 घोषित करता है।
4. **राजनीतिक समानता:** प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार है, जिसे "एक व्यक्ति, एक मत" कहा जाता है। भारत में अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है।
5. **आर्थिक समानता:** धन और आय का उचित वितरण तथा अत्यधिक गरीबी से मुक्ति। यह समान आय की माँग नहीं करती, किंतु अनुच्छेद 39 राज्य को धन के संकेंद्रण से बचने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है।
6. **अवसर की समानता:** शिक्षा और रोज़गार में सबको उचित अवसर मिले, जैसे अनुच्छेद 16 और 21क में, तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

स्वतंत्रता और समानता का संबंध

इस विषय पर चिंतन की दो परंपराएँ हैं।

1. स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं (उदारवादी मत)। लॉर्ड एक्टन और द टॉकविल जैसे विचारकों को भय था कि अत्यधिक समानता स्वतंत्रता घटा देगी। यदि राज्य समान आय लागू करे, तो उसे प्रतिभाशाली या परिश्रमी व्यक्तियों की अधिक कमाने की स्वतंत्रता सीमित करनी होगी। उनके अनुसार समान परिणाम केवल चयन पर नियंत्रण से मिल सकते हैं।

2. स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं (लोकतांत्रिक और समाजवादी मत)। रूसो, लास्की, आर. एच. टॉनी और अंबेडकर ने तर्क दिया कि समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है।

- राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली है यदि गरीब उसका उपयोग न कर सकें: भूखे व्यक्ति का मतदान का अधिकार धनी व्यक्ति के प्रभाव के बराबर नहीं होता।
- आर्थिक असमानता धनी को निर्धन पर शक्ति देती है, इसलिए वह बहुसंख्यकों की स्वतंत्रता नष्ट करती है।
- अवसर की समानता स्वयं अपनी योग्यताओं के विकास की वास्तविक स्वतंत्रता की शर्त है।
- अंबेडकर ने चेताया कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता, और कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक "त्रिमूर्ति का संघ" हैं; एक को दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता।

मूल्यांकन

सर्वोत्तम समाधान यह है कि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। परिणामों की पूर्ण समानता स्वतंत्रता और दक्षता को हानि पहुँचाएगी, जबकि असीमित स्वतंत्रता शक्तिशाली के प्रभुत्व को जन्म देगी। इसलिए न्यायपूर्ण समाज सबके लिए **समान स्वतंत्रता** सुनिश्चित करता है: समान मूल अधिकार, समान अवसर और जीवन का न्यूनतम स्तर, तथा परिश्रम से अर्जित अंतर के लिए स्थान। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत भी ऐसा ही संतुलन दर्शाते हैं।

तुलना

पक्ष	स्वतंत्रता	समानता
मूल विचार	प्रतिबंध से मुक्ति और विकास की स्वतंत्रता	समान मूल्य और समान अवसर
अति होने पर मुख्य खतरा	बलवान का प्रभुत्व	एकरूपता, चयन का अभाव
संवैधानिक उदाहरण	अनुच्छेद 19	अनुच्छेद 14-17

निष्कर्ष

समानता लोकतंत्र का आवश्यक आधार है और यह तभी सार्थक है जब स्वतंत्रता से जुड़ी हो। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों के द्वारा दोनों को पाने का प्रयास करता है। लक्ष्य ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान गरिमा और वह बनने का वास्तविक अवसर मिले जो वह बन सकता है।

प्रश्न 5 (अथवा) · इकाई 3 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

सविनय अवज्ञा क्या है? इसकी आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए, इसे साधारण अपराध और क्रांति से अलग कीजिए तथा बताइए कि लोकतंत्र में यह कहाँ तक उचित है।

प्रस्तावना

जो नागरिक किसी कानून से असहमत होता है, उसके पास सामान्यतः वैध उपाय होते हैं: मतदान, याचिकाएँ, सार्वजनिक बहस और न्यायालय। फिर भी कभी-कभी कोई व्यक्ति किसी कानून या नीति को इतना अन्यायपूर्ण

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

मानता है कि वह सार्वजनिक रूप से जानबूझकर उसका उल्लंघन करता है। इस कृत्य को **सविनय अवज्ञा** कहते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत का मूल प्रश्न उठाती है: नागरिक नैतिक रूप से राज्य की अवज्ञा कब, यदि कभी, कर सकता है?

अर्थ और परिभाषा

सविनय अवज्ञा किसी कानून या नीति का खुला, शांतिपूर्ण और अंतरात्मा-प्रेरित उल्लंघन है, जिसमें कानूनी दंड स्वीकार किया जाता है, ताकि अन्याय की ओर ध्यान खींचा जा सके और कानून में परिवर्तन हो। जॉन रॉल्स ने *ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस* (1971) में इसे कानून के विरुद्ध एक सार्वजनिक, अहिंसक, अंतरात्मा-प्रेरित और राजनीतिक कृत्य बताया है, जिसका उद्देश्य प्रायः कानून या सरकारी नीति को बदलना होता है। यह *अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वाले (कंसेंशियस ऑब्जेक्टर)* के निजी इनकार से भिन्न है, जो केवल अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखना चाहता है और कानून बदलने का प्रयास नहीं करता।

सविनय अवज्ञा, अपराध और क्रांति

सविनय अवज्ञा	साधारण अपराध	क्रांति
नैतिक उद्देश्य	निजी लाभ	व्यवस्था बदलना
शांतिपूर्ण और खुला	प्रायः गुप्त	प्रायः हिंसक
दंड स्वीकार करती है	दंड से बचता है	दंड अस्वीकार
एक अन्यायपूर्ण कानून	कोई जनहित नहीं	संपूर्ण शासन

सविनय अवज्ञा की तुलना साधारण अपराध और क्रांति से

आवश्यक शर्तें

1. **अहिंसा:** व्यक्तियों या संपत्ति को कोई हानि नहीं; विरोध समझाता है, बाध्य नहीं करता।
2. **खुलापन:** यह गुप्त रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से किया जाता है ताकि अधिकारी और जनता कारण जान सकें।
3. **अंतरात्मा-प्रेरित उद्देश्य:** यह गंभीर अन्याय और जनहित के लिए होती है, निजी लाभ के लिए नहीं।
4. **दंड की स्वीकृति:** विरोध करने वाला दंड से भागता नहीं; उसकी कष्ट सहने की इच्छा उसकी ईमानदारी और समग्र कानून के प्रति उसके सम्मान को दर्शाती है।
5. **अंतिम उपाय:** याचिका, वार्ता और न्यायालय जैसे वैध उपाय प्रायः आज़माए जा चुके होते हैं और विफल रहे होते हैं।
6. **सीमित लक्ष्य:** यह किसी एक अन्यायपूर्ण कानून या नीति का विरोध करती है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था का नहीं।

उदाहरण

- **हेनरी डेविड थोरो** ने आंशिक रूप से दासता और मैक्सिकन युद्ध के विरोध में मतदान-कर (पोल टैक्स) देने से इनकार किया। उन्होंने एक रात जेल में बिताई (1846) और अपने विचार निबंध *रेज़िस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट* (1849) में रखे, जो बाद में *सिविल डिसओबिडिएंस* के नाम से जाना गया।
- **महात्मा गांधी** ने इस पद्धति को *सत्याग्रह*, अर्थात सत्य पर दृढ़ रहने के रूप में विकसित किया। इसका प्रयोग चंपारण (1917), असहयोग आंदोलन (1920-22) और साबरमती से दांडी तक नमक यात्रा (12 मार्च से 6 अप्रैल 1930) में हुआ, जिसके बाद देशभर में स्वयंसेवकों ने नमक कानून तोड़ा और बिना प्रतिशोध के लाठियाँ और कारावास सहे।
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर** ने इसे मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार (1955-56) में अपनाया और *लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल* (1963) में इसका समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण कानून को

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

खुलेआम तोड़ता है और दंड स्वीकार करता है, वह कानून के प्रति सर्वोच्च सम्मान दिखाता है।

अपराध और क्रांति से अंतर

आधार	सविनय अवज्ञा	साधारण अपराध	क्रांति
उद्देश्य	नैतिक, जनहित	निजी लाभ	संपूर्ण व्यवस्था बदलना
तरीका	शांतिपूर्ण और खुला	प्रायः गुप्त	प्रायः हिंसक
दंड	स्वीकार	बचाव	अस्वीकार
लक्ष्य	एक अन्यायपूर्ण कानून	कोई नहीं	संपूर्ण शासन
कानून के प्रति सम्मान	बना रहता है	नहीं	अस्वीकार

क्या लोकतंत्र में यह उचित है?

पक्ष में: गंभीर रूप से अन्यायपूर्ण कानून का पालन करना स्वयं एक नैतिक समझौता है; बहुमत भूल कर सकता है या अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीन हो सकता है; और शांतिपूर्ण अवज्ञा जनता की अंतरात्मा को जगाती है, जैसा गांधीजी के आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किया। रॉल्स जोड़ते हैं कि लगभग न्यायपूर्ण समाज में यह बहुमत की अपनी न्याय-भावना से अपील करके न्याय को मज़बूत कर सकती है।

विपक्ष में: लोकतंत्र में कानून बदलने के वैध तरीके मौजूद हैं; यदि हर नागरिक स्वयं तय करे कि कौन-सा कानून माने तो व्यवस्था ढह जाएगी; विरोध हिंसा में बदल सकता है; और अवज्ञा करने वाला व्यक्ति इस बारे में गलत हो सकता है कि क्या न्यायपूर्ण है।

संतुलित दृष्टि: सविनय अवज्ञा केवल गंभीर अन्याय के विरुद्ध, वैध उपाय विफल होने के बाद, और तब उचित है जब वह अहिंसक, सार्वजनिक और दंड स्वीकार करने को तैयार हो। भारत में अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन; इसलिए शांतिपूर्ण विरोध वैध है, परंतु जानबूझकर कानून तोड़ना दंडनीय रहता है और प्रत्येक मामले का निर्णय न्यायालय करते हैं।

निष्कर्ष

सविनय अवज्ञा विधि-शासन की शत्रु नहीं, बल्कि जैसा कानून है उससे जैसा होना चाहिए उसकी ओर एक अंतरात्मा-प्रेरित अपील है। यदि इसका प्रयोग कम, शांतिपूर्वक और गंभीर अन्याय के विरुद्ध हो तो यह लोकतंत्र को मज़बूत कर सकती है; लापरवाही से प्रयोग हो तो यह सभी कानूनों के प्रति सम्मान को कमज़ोर कर सकती है।

प्रश्न 6 • इकाई 4 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

सर्वाधिकारवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए और इसे लोकतंत्र से अलग कीजिए।

प्रस्तावना

सर्वाधिकारवाद शासन का वह रूप है जिसमें राज्य केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि निजी जीवन को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह शब्द 1920 के दशक में इटली में मुसोलिनी के आलोचकों ने पहली बार प्रयोग किया, और मुसोलिनी ने स्वयं इसे गर्व से इस सूत्र में अपनाया: "सब कुछ राज्य के भीतर, कुछ भी राज्य के बाहर नहीं, कुछ भी राज्य के विरुद्ध नहीं।" इसके उत्कृष्ट उदाहरण हिटलर का नाज़ी जर्मनी, फ़ासीवादी इटली और स्तालिन का सोवियत संघ हैं।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

अर्थ

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था वह है जहाँ एक दल और एक नेता के पास असीमित शक्ति होती है, सब पर एक आधिकारिक विचारधारा थोपी जाती है, और व्यक्ति राज्य की सेवा के लिए होता है। व्यक्ति के पास निजी स्वतंत्रता का कोई क्षेत्र नहीं होता। हाना आरेंट की *द ओरिजिंस ऑफ़ टोटैलिटेरियनिज़्म* (1951) तथा कार्ल फ्रेडरिक और ज़बिग्न्यू ब्रेज़िंस्की का कार्य इसके मानक अध्ययन हैं।

मुख्य विशेषताएँ

1. **एकदलीय शासन:** केवल एक दल, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च नेता करता है, मान्य होता है। अन्य सभी दल प्रतिबंधित होते हैं और दल राज्य में विलीन हो जाता है।
2. **आधिकारिक विचारधारा:** नाज़ीवाद, फ़ासीवाद या मार्क्सवाद-लेनिनवाद जैसा एक सिद्धांत सब कुछ समझाता है और स्कूलों व मीडिया से सबको पढ़ाया जाता है।
3. **तानाशाह और व्यक्ति-पूजा:** नेता को अचूक दिखाया जाता है। "फ्यूहरर हमेशा सही है" जैसे नारे आम थे।
4. **अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण:** राज्य स्वामित्व या कठोर नियंत्रण से उत्पादन और श्रम को निर्देशित करता है।
5. **मीडिया और शिक्षा पर नियंत्रण:** समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा और स्कूल प्रचार के लिए प्रयोग होते हैं और स्वतंत्र चिंतन सहन नहीं किया जाता।
6. **गुप्त पुलिस और आतंक:** जर्मनी में गेस्टापो और सोवियत संघ में एन.के.वी.डी. ने गिरफ़्तारियों, शिविरों और मृत्युदंड से भय फैलाया।
7. **अधिकार और विपक्ष नहीं:** भाषण, सभा और संगठन की स्वतंत्रता दबा दी जाती है और न्यायालय स्वतंत्र नहीं रहते।
8. **सैन्यवाद और विस्तार:** युद्ध और राष्ट्रीय गौरव का महिमामंडन होता है और जन-लामबंदी आम है।
9. **नागरिक समाज का विनाश:** क्लब, यूनियन और चर्च नियंत्रित या भंग कर दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति और राज्य के बीच कुछ न रहे।

लोकतंत्र और सर्वाधिकारवाद

लोकतंत्र	सर्वाधिकारवाद
शक्ति जनता से आती है	शक्ति एक दल या नेता के पास
स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव	वास्तविक चुनाव नहीं
अधिकार व विपक्ष की अनुमति	अधिकार व विपक्ष का दमन
स्वतंत्र न्यायपालिका व प्रेस	न्यायालय व मीडिया नियंत्रित
सीमित, उत्तरदायी सरकार	जीवन पर पूर्ण नियंत्रण

लोकतंत्र और सर्वाधिकारवाद की तुलना

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र

आधार	लोकतंत्र	सर्वाधिकारवाद
शक्ति का स्रोत	जनता	नेता या दल
दल	अनेक; विपक्ष की अनुमति	केवल एक दल
चुनाव	स्वतंत्र व निष्पक्ष	अनुपस्थित या नकली
अधिकार	सुरक्षित	दबाए गए
न्यायपालिका और प्रेस	स्वतंत्र	नियंत्रित
व्यक्ति	स्वयं साध्य	राज्य का साधन
सरकार का परिवर्तन	शांतिपूर्ण, मत द्वारा	तख्तापलट या मृत्यु से
विचारधारा	बहुल	एक आधिकारिक विचारधारा
सरकार	सीमित, उत्तरदायी	असीमित, अनुत्तरदायी

सर्वाधिकारवाद और निरंकुशतावाद

निरंकुश शासक भी लोकतंत्र को नकारते हैं, परंतु प्रायः समाज, धर्म और निजी जीवन को अकेला छोड़ देते हैं। सर्वाधिकारवादी शासक जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने और बदलने तथा हर नागरिक को विचारधारा के द्वारा लामबंद करने का प्रयास करते हैं।

आलोचना

- यह स्वतंत्रता, गरिमा और मानवाधिकारों को नष्ट करता है।
- यह सहमति पर नहीं, भय पर टिका है, इसलिए इसमें वास्तविक वैधता नहीं होती।
- बुरे शासक को हटाने का कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं होता।
- यह रचनात्मकता, विज्ञान और कला को दबाता है।
- इसने प्रायः युद्ध और सामूहिक हत्याओं को जन्म दिया, जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध और होलोकॉस्ट में।

उत्थान के कारण

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपमान, महामंदी जैसा आर्थिक संकट, साम्यवाद का भय, उग्र राष्ट्रवाद और कमज़ोर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने इटली और जर्मनी में सर्वाधिकारवादी आंदोलनों को उभरने में सहायता की।

निष्कर्ष

सर्वाधिकारवाद लोकतांत्रिक शासन का विपरीत है। यह व्यक्ति को साधन मानता है और शासक को अनियंत्रित शक्ति देता है। 1945 में नाज़ी और फ़ासीवादी शासनों का पतन तथा 1991 में सोवियत व्यवस्था का अंत दिखाते हैं कि भय पर आधारित शासन अस्थिर होते हैं। अधिकार, स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायालय वाला लोकतंत्र ऐसे शासन की वापसी के विरुद्ध सुरक्षा बना हुआ है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 6 (अथवा) • इकाई 4 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा बहुमत प्रणाली की तुलना आनुपातिक प्रतिनिधित्व से कीजिए।

प्रस्तावना

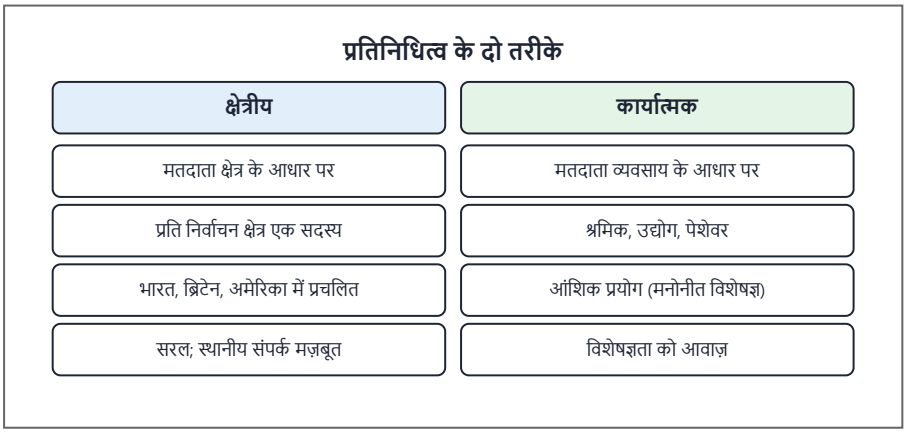
करोड़ों लोगों वाले आधुनिक राज्य में सभी नागरिक प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों की तरह एक साथ बैठकर कानून नहीं बना सकते। इसलिए लोकतंत्र **प्रतिनिधित्व** के माध्यम से चलता है: जनता कुछ व्यक्तियों को अपनी ओर से बोलने और निर्णय लेने के लिए चुनती है। दो प्रश्न उठते हैं: प्रतिनिधि किसका प्रतिनिधित्व करें और उन्हें कैसे चुना जाए? पहले का उत्तर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत देते हैं और दूसरे का निर्वाचन प्रणाली।

अर्थ

प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि कुछ निर्वाचित व्यक्ति अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं। एडमंड बर्क ने ब्रिस्टल के मतदाताओं को दिए भाषण (1774) में कहा कि प्रतिनिधि मतदाताओं को अपना विवेक देता है और उसे मात्र प्रतिनिधि-दूत नहीं बनना चाहिए।

प्रतिनिधित्व के सिद्धांत

1. **न्यासी (बर्क का) सिद्धांत:** प्रतिनिधि बुद्धिमान न्यासी है जो राष्ट्रीय हित में अपना विवेक प्रयोग करता है, चाहे मतदाताओं की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो।
2. **प्रतिनिधि-दूत (जनादेश) सिद्धांत:** प्रतिनिधि एक एजेंट है जो अपने मतदाताओं के निर्देश पूरे करता है, जैसे दल के घोषणा-पत्र और जनादेश की धारणा में।
3. **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व:** मतदाता भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर समूहित होते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अपना सदस्य चुनता है। यह भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित है।
4. **कार्यात्मक (व्यावसायिक) प्रतिनिधित्व:** मतदाता श्रमिक, उद्योग और पेशेवर जैसे व्यवसायों के आधार पर समूहित होते हैं ताकि प्रत्येक हित को स्वर मिले। गिल्ड समाजवादियों और जी. डी. एच. कोल ने इसका समर्थन किया। भारत में राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन इसे केवल सीमित रूप में दर्शाता है।
5. **मार्क्सवादी मत:** पूँजीवादी राज्य में प्रतिनिधित्व मुख्यतः शासक वर्ग की सेवा करता है।
6. **वर्णनात्मक और समूह प्रतिनिधित्व:** विधायिका को जनसंख्या का प्रतिबिंब होना चाहिए, इसलिए भारत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।



क्षेत्रीय और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व

निर्वाचन प्रणालियाँ

क. बहुमत प्रणाली।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- *एकल-सदस्यीय बहुलता (फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट):* निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत पाने वाला प्रत्याशी जीतता है, चाहे उसे बहुमत न मिले। लोकसभा के लिए यही प्रयुक्त है।
- *द्वितीय मतदान:* यदि किसी को पूर्ण बहुमत न मिले तो शीर्ष प्रत्याशियों के बीच दूसरा चरण होता है, जैसे फ्रांस में।

ख. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पी.आर.)। सीटें मतों के अनुपात में बाँटी जाती हैं। *एकल संक्रमणीय मत* (हेयर प्रणाली) में मतदाता बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों को वरीयता क्रम देते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में यह प्रणाली अपने वरीयता-मत रूप में प्रयुक्त है। *सूची प्रणाली* इज़राइल और नीदरलैंड जैसे देशों में प्रयुक्त है।

बहुमत प्रणाली के गुण-दोष

गुण	दोष
सरल और समझने में आसान	विजेता को आधे से कम मत मिल सकते हैं
निर्वाचन क्षेत्र से सीधा संबंध	हारने वाले प्रत्याशियों के मत व्यर्थ जाते हैं
स्थिर, एकदलीय सरकार देती है	छोटे दलों और अल्पसंख्यकों का कम प्रतिनिधित्व
द्विदलीय प्रणाली को प्रोत्साहन	सीटें मत-प्रतिशत से मेल नहीं खातीं

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण-दोष

गुण	दोष
हर मत की गिनती	जटिल मतगणना
अल्पसंख्यकों और छोटे दलों को सीटें	अनेक दलों और गठबंधनों को बढ़ावा
सीटें मत-प्रतिशत के अनुरूप	सदस्य का स्थानीय संपर्क कमज़ोर
अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष	सरकार अस्थिर हो सकती है

तुलना

आधार	बहुमत प्रणाली	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
निर्वाचन क्षेत्र	एकल-सदस्यीय	बहु-सदस्यीय
परिणाम	विजेता सब पाता है	मत-अनुपात से सीटें
दल प्रणाली	दो दलों के अनुकूल	अनेक दलों के अनुकूल
सरकार	प्रायः स्थिर	प्रायः गठबंधन
उदाहरण	लोकसभा, ब्रिटेन	इज़राइल, नीदरलैंड

भारतीय स्थिति

संविधान सभा ने भारत के आकार, उस समय की कम साक्षरता और कई छोटे दलों से अस्थिरता के भय के कारण लोकसभा के लिए पी.आर. को अस्वीकार किया। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बहुलता मतदान प्रयुक्त है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनावों में एकल संक्रमणीय मत प्रयुक्त है।

निष्कर्ष

कोई भी निर्वाचन प्रणाली पूर्ण नहीं है। बहुमत प्रणाली स्थिरता और स्थानीय उत्तरदायित्व देती है पर अल्पसंख्यकों के प्रति अन्यायपूर्ण हो सकती है, जबकि पी.आर. अधिक निष्पक्ष है पर अस्थिरता ला सकती है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

इसलिए कई देश मिश्रित प्रणालियाँ अपनाते हैं, जैसे जर्मनी। प्रणाली जो भी हो, प्रतिनिधित्व के अच्छे सिद्धांत की माँग है कि निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी रहें और सभी वर्गों के हितों की रक्षा करें।

DEMO SAMPLE · ONLINE STUDENT SEVA

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Exam Strategy परीक्षा रणनीति

1. Political Theory answers score on clear concepts: start every answer with a one-line definition and name the thinker with the book and year only when you are sure of it.
2. For a 10-mark answer keep a fixed pattern: introduction, 4-5 headed points, a comparison table, a short critical evaluation and a conclusion.
3. Learn the thinkers in pairs (Hobbes-Locke-Rousseau, Austin-Laski, Berlin's two liberties) so you can write comparison answers quickly.
4. Use Indian examples (the Constitution of India, Gandhi, Ambedkar, Indian elections) wherever the question allows; examiners reward application.
5. Draw the small diagram or table given in the model answer; a neat figure in a theory paper stands out.
6. Practise writing one long answer in 25 minutes and one short answer in 6 minutes; time management decides the last question.
7. Do not depend on this demo or any single paper: finish the full syllabus from the prescribed books.

1. राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर स्पष्ट अवधारणा पर अंक पाते हैं: हर उत्तर की शुरुआत एक पंक्ति की परिभाषा से करें और चिंतक, पुस्तक व वर्ष तभी लिखें जब आप निश्चित हों।
2. 10 अंक के उत्तर में निश्चित ढाँचा रखें: भूमिका, 4-5 शीर्षकयुक्त बिंदु, तुलना तालिका, संक्षिप्त मूल्यांकन और निष्कर्ष।
3. चिंतकों को जोड़ियों में याद करें (हॉब्स-लॉक-रूसो, ऑस्टिन-लास्की, बर्लिन की दो स्वतंत्रताएँ) ताकि तुलनात्मक उत्तर जल्दी लिख सकें।
4. जहाँ प्रश्न अनुमति दे, भारतीय उदाहरण (भारतीय संविधान, गांधी, अंबेडकर, भारतीय चुनाव) दें; परीक्षक व्यावहारिक समझ को सराहते हैं।
5. मॉडल उत्तर में दिया गया छोटा चित्र या तालिका स्वयं बनाएँ; सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में साफ चित्र अलग दिखता है।
6. एक दीर्घ उत्तर 25 मिनट में और एक लघु उत्तर 6 मिनट में लिखने का अभ्यास करें; अंतिम प्रश्न समय-प्रबंधन से तय होता है।
7. इस डेमो या किसी एक पेपर पर निर्भर न रहें: निर्धारित पुस्तकों से पूरा पाठ्यक्रम पूरा करें।

Final reminder / अंतिम सलाह: Even though this paper covers high-probability topics, do not depend on it fully — revise the entire syllabus. इस पर पूरी तरह निर्भर न रहें; पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें।
Online Student Seva · Pariksha Pass App · Edition Oct 2026

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Like the answer quality? उत्तरों की गुणवत्ता पसंद आई?

Unlock the full sets in the Pariksha Pass App

This Demo Set shows the real paper format and answer quality for **Introduction to Political Theory**. The complete Guessing Paper for your university gives you, for this subject:

- ✓ **3 full sets** – Set A (Most Probable), Set B (Highly Likely) and Set C (Alternate)
- ✓ **30 objective, 15 short-answer and 24 long-answer questions** with model answers, in English and in Hindi
- ✓ Every unit of the syllabus covered, with labelled diagrams, tables and worked examples
- ✓ An exam-style question paper with your university's header, a syllabus coverage table and a book list
- ✓ An "Asked in" tag wherever a question matches a past university paper

पूर्ण गेसिंग पेपर में : इसी विषय के 3 पूर्ण सेट (A, B, C), 30 वस्तुनिष्ठ, 15 लघु उत्तर तथा 24 दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न — सभी आदर्श उत्तरों सहित, अंग्रेज़ी व हिन्दी दोनों में; पूरे पाठ्यक्रम की सभी इकाइयाँ, चित्र, तालिकाएँ और हल किए गए उदाहरण।

Available only in the Pariksha Pass App. Open the app, choose your university, course, semester and subject, and unlock your paper. केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध — ऐप खोलें, अपना विश्वविद्यालय, कोर्स, सेमेस्टर और विषय चुनें और अपना पेपर अनलॉक करें।

Please note / ध्यान दें: The questions in this Demo Set are **not** the questions of the actual Set A, B or C; they are sample questions from the same syllabus, written to show the paper format and the answer quality. इस डेमो सेट के प्रश्न वास्तविक सेट A, B, C के प्रश्न नहीं हैं; ये उसी पाठ्यक्रम के नमूना प्रश्न हैं, जो केवल पेपर का प्रारूप व उत्तरों की गुणवत्ता दिखाने के लिए बनाए गए हैं।

Our sets focus on high-probability topics, but no paper can promise what will be asked — use them for practice along with your text book. हमारे सेट अधिक संभावित टॉपिक पर केंद्रित हैं, पर कोई भी पेपर यह वादा नहीं कर सकता कि क्या पूछा जाएगा — पाठ्यपुस्तक के साथ अभ्यास के लिए उपयोग करें।

Online Student Seva · Pariksha Pass App · Demo edition Oct 2026

Download Pariksha Pass App >

Get all 3 full Guessing Paper sets on Google Play

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।